page 1 and 8 July 11_page 1 Mar 25 final ds.qxd 7/11/2026 1:59 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 जम्मू फिल्म महोत्सव को दुनिया भर से जबरदस्त प्रतिक्रिया

5 मोहम्मद नबी के बेटे का तूफान, सिर्फ28 गेंदों पर जड़ा शतक

8 डिजिटल भारत निधि की समीक्षा-डीसी कठुआ ने पहाड़ी क्षेत्रों में तेज इंटरनेट विस्तार पर दिया जोर

न्यूनतम 22

मौसम जम्मू

अधिकतम 36

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-172 | जम्मू तवी, शनिवार 11 जुलाई, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

1996 श्रीनगर हिंसा मामले में एनआईए ने हुर्रियत के छह अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

नई दिल्ली, 10 जुलाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को वर्ष 1996 में श्रीनगर में भीड़ हिंसा और पुलिस कर्मियों पर फायरिंग से जुड़े मामले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के छह अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इनमें शब्बीर अहमद शाह भी शामिल हैं।

जांच एजेंसी द्वारा जारी बयान के अनुसार, जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में शब्बीर अहमद शाह के अलावा सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील उर्फ मोहम्मद याकूब वकील, जाविद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी को भी आरोपी बनाया गया है।

एनआईए के अनुसार, सभी छह आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने, हत्या के प्रयास, दंगा करने तथा लोक सेवकों पर हमला करने के आरोप लगाए गए हैं।

हालांकि, सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन और मोहम्मद याकूब वकील का कार्यवाही के दौरान निधन हो जाने के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद एनआईए का दावा है कि आरोप पत्र में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आपराधिक साजिश और गैरकानूनी जमावड़े के साझा उद्देश्य में उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित की गई है।

एनआईए की जांच में सामने आया कि 17 जुलाई 1996 को श्रीनगर में मारे गए आतंकवादी हिलाल अहमद बेग के जनाजे के दौरान इन छह आरोपियों ने गैरकानूनी भीड़ का नेतृत्व किया और पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काई।

जांच एजेंसी का कहना है कि विस्तृत जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि यह भीड़ हिंसा हुर्रियत नेतृत्व की एक बड़ी और पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश का हिस्सा थी।

जांच एजेंसी के अनुसार, जनाजे के जुलूस में हथियारबंद आतंकवादी भी भीड़ में शामिल थे। आरोप है कि हुर्रियत नेताओं के संयुक्त नेतृत्व में निकाले गए इस जुलूस के दौरान आतंकवादियों ने पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए। भारी पथराव के कारण सरकारी वाहनों को भी व्यापक नुकसान पहुंचा।

एनआईए के निष्कर्षों के अनुसार, आरोपित हुर्रियत नेताओं ने हिंसा के दौरान भारत विरोधी, पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी नारे लगाए तथा लोगों को भड़काने वाले भाषण दिए, जिनमें सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया गया।

जांच एजेंसी का कहना है कि विस्तृत जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि यह भीड़ हिंसा हुर्रियत नेतृत्व की एक बड़ी और पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश का हिस्सा थी। आरोप है कि जनाजे के जुलूस का इस्तेमाल अलगाववादी विचारधारा के प्रचार, भारत सरकार के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने, सार्वजनिक अशांति फैलाने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ हिंसा भड़काने तथा जम्मू-कश्मीर में हुर्रियत की ताकत का प्रदर्शन करने के मंच के रूप में किया गया।

इस मामले में हिंसा वाले दिन श्रीनगर के शेरगढ़ी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने अप्रैल 2026 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

मनोज सिन्हा ने बालटाल बेस कैंप का दौरा कर अमरनाथ यात्रियों से की बातचीत

बालटाल, 10 जुलाई ।जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को बालटाल बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और यात्रियों से बातचीत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन जिसमें पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से चले। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि श्रद्धालु सुखद अनुभव के साथ लौटें।

उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से टेंट में रहने की व्यवस्था का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सुविधाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यह यात्रा अपने कुशल प्रबंधन के लिए याद की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि व्यवस्थाओं में और सुधार होता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बालटाल और चंदनवाड़ी में 100-बिस्तरों वाले अस्पताल पिछले तीन वर्षों से काम कर रहे हैं और यात्रियों तथा यात्रा ड्यूटी में लगे कर्मियों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहे हैं।

उपरायपाल ने घायल अमरनाथ यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना

श्रीनगर, 10 जुलाई । उपरायपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि अमरनाथ की यात्रा पर निकले छह तीर्थयात्री उधमपुर जिले के तोल्डी नाले के पास एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। पहलगाम बेस कैंप जाते समय उनका वाहन सड़क से फिसल गया। एलजी सिन्हा ने एक पोस्ट में लिखा, मुझे मध्य प्रदेश के रीवा से आ रहे श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर निकले 6 तीर्थयात्रियों के साथ उधमपुर के तोल्डी नाले के पास हुई सड़क दुर्घटना की सूचना मिली है। श्रद्धालु पवित्र गुफा दर्शन के लिए पहलगाम बेस कैंप जा रहे थे तभी उनका वाहन सड़क से फिसल गया। एक तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल है जबकि अन्य पांच की हालत स्थिर है और वर्तमान में उन्हें उधमपुर जीएमसी में इलाज मिल रहा है। गंभीर रूप से घायल तीर्थयात्री को जीएमसी जम्मू में स्थानांतरित कर दिया गया है। पोस्ट में आगे लिखा है, मैंने जम्मू के संभागीय आयुक्त, उधमपुर के उपायुक्त और जीएमसी जम्मू और उधमपुर के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उन्हें सर्वोत्तम संभव उपचार मिले। मैं भगवान शिव से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

खबर संक्षेप

पुलिस ने जेकेएनओपी से जुड़े व्यक्तियों, उनके पारिवारिक आवासों तथा उनसे संबंधित अन्य परिसरों में चलाया तलाशी अभियान

बारामुला, 10 जुलाई । जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से बारामूला पुलिस ने आज थाना क्रीरी, थाना बोनियार और पुलिस पोस्ट कमलकोट के अधिकार क्षेत्र में जेकेएनओपी से जुड़े व्यक्तियों, उनके पारिवारिक आवासों तथा उनसे संबंधित अन्य परिसरों में समन्वित तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान विधि के प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की निगरानी तथा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में संचालित किया गया जिससे पूरी कार्रवाई के दौरान कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

तलाशी अभियान का उद्देश्य आवश्यक खुफिया जानकारी एकत्र करना, हालिया गतिविधियों का पता लगाना, सीमा पार मौजूद हैंडलरों के साथ संभावित संपर्कों या संचार की जांच करना तथा किसी भी प्रकार की गैरकानूनी अथवा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने या उन्हें बढ़ावा देने के प्रयासों को रोकना था।

बारामूला पुलिस जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुरक्षा संबंधी खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने तथा जिले में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे कानूनी अभियान जारी रहेंगे।

कश्मीर में बाढ़ सुरक्षा व सिंचाई ढांचे को मजबूत करने के निर्देश

श्रीनगर, 10 जुलाई । जल शक्ति, वन पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने सिविल सचिवालय श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक कर कश्मीर संभाग में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण सेक्टर की समीक्षा की।

बैठक में मंत्री राणा ने झेलम नदी और उसकी सहायक नदियों के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चल रहे कार्यों को गुणवत्ता और तय समयसीमा के भीतर तेजी से पूरा किया जाए ताकि मानसून से पहले आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने सिंचाई नहरों की मरम्मत, बंद पड़ी योजनाओं को पुनः चालू करने और किसानों को निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।

वहीं सलाहकार नासिर असलम वानी ने बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक रणनीति, तटबंधों की मजबूती और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं जबकि दूसरे चरण के अंतर्गत 1623.43 करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं। वर्ष 2026-27 के लिए 129 कार्यों पर काम किया जा रहा है जिनमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर में केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की

लाभार्थी आधारित योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश

श्रीनगर, 10 जुलाई। मुख्य सचिव अतल डुल्लू ने संबंधित प्रशासनिक सचिवों के साथ लंबी समीक्षा बैठक कर जम्मू-कश्मीर में केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजनाओं (सीएसएस) और विभिन्न प्रमुख आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रगति का विस्तृत आकलन किया। बैठक के दौरान संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों ने अपनी-अपनी योजनाओं के तहत हासिल की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों, क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों तथा भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्य सचिव ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रामीण एवं शहरी विकास, आवास, सामाजिक कल्याण, वित्त, पर्यटन, कौशल विकास, पेयजल, परिवहन, मत्स्य पालन तथा आधारभूत ढांचा विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रमुख योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जनसेवाओं में सुधार तथा केंद्र शासित प्रदेश में समावेशी सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिणाम आधारित सुशासन पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की नियमित निगरानी करने, क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर करने तथा उपलब्ध धनराशि का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने प्रशासनिक सचिवों से कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने तथा जमीनी स्तर पर लगातार निगरानी रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

मुख्य सचिव ने कई प्रमुख योजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक तेजी से कार्य करें।

अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने सांबा में सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया

जम्मू, 10 जुलाई । अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के तहत शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के सांबा ज़िले में पुलिस ने सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज़ (इलाके पर नियंत्रण की कवायद) की और रेलवे ट्रैक की सुरक्षा की जांच की।

गुफा मंदिर की 57 दिनों की यह तीर्थयात्रा 3 जुलाई को अनंतनाग ज़िले में 48 किलोमीटर लंबे नुनवान-पहलगाम रूट और गांदरबल ज़िले में 14 किलोमीटर लंबे और ज़्यादा ढलान वाले बालटाल रूट से शुरू हुई थी और यह 28 अगस्त को खत्म होगी। इसलिए यह ऑपरेशन सांबा के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस की देखरेख में नोनाथ खड्ड और घगवाल के संवेदनशील इलाकों और उनसे सटे रेलवे ट्रैक पर चलाया गया। इस कवायद में सांबा के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप सीआरपीएफ की 93वीं बटालियन और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने संवेदनशील जगहों पर सघन तलाशी ली और इलाके में मौजूद एक खाली पड़ी इमारत में भी सीएएसो चलाया, ताकि यह पक्का किया जा सके कि असामाजिक या देश-विरोधी तत्व उसका इस्तेमाल न कर सकें। रेल संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी के साथ मिलकर इलाके से गुज़रने वाले रेलवे ट्रैक की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल की गई। ऑपरेशन के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तैनात पुलिसकर्मियों को ज़रूरी निर्देश दिए गए।

अमरनाथ गुफा के लिए 8,500 से यादा तीर्थयात्रियों का नौवां जत्था जम्मू से रवाना

जम्मू, 10 जुलाई । अमरनाथ गुफा के लिए 8,500 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का नौवां जत्था शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा मंदिर के दो बेस कैंपों के लिए रवाना हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह 8,796 तीर्थयात्री जम्मू बेस कैंप से 354 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए जिनमें हल्की और भारी मोटर गाड़ियां शामिल थीं। इस जत्थे में बालटाल के लिए 3,450 और पहलगाम के लिए 5,346 तीर्थयात्री शामिल थे। वे कई स्तरों वाले सुरक्षा घेरे में यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए नागरिक प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने

मिलकर इंतज़ाम किए थे।

यात्रा शुरू होने के बाद से पिछले सात दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से कुल 1,71,501 तीर्थयात्रियों ने गुफा मंदिर के दर्शन किए हैं। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे कन्फर्म रजिस्ट्रेशन और यात्रा की तय तारीख पर ही यात्रा करें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन वाले किसी भी तीर्थयात्री को बेस कैंप तक जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

जम्मू-कश्मीर में 11 से 12 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना

श्रीनगर 10 जुलाई । वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून के कम दबाव वाले सिस्टम के आपस में मिलने से 11-13 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर में बारिश बढ़ने की उम्मीद है जिसमें 11-12 जुलाई को बारिश सबसे ज्यादा हो सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक आम तौर पर गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान भी लगाया है। साथ ही बीच-बीच में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने संवेदनशील इलाकों में भारी बारिश और संभावित भूस्खलन के लिए चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर के अनुसार 10 जुलाई को मौसम आम तौर पर गर्म और उमस भरा रहेगा और कुछ जगहों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। जम्मू डिवीजन में कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश होने की संभावना है। 11-12 जुलाई को कई जगहों पर एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। जम्मू डिवीजन की चिनाब घाटी और पीर पंजाल रेंज में कुछ जगहों पर भारी बारिश और थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है।

मैराथन

मुख्यमंत्री उमर ने कश्मीर मैराथन 2026 की आधिकारिक सामग्री और प्रचार अभियान का शुभारंभ किया

श्रीनगर, 10 जुलाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कश्मीर मैराथन 2026 की आधिकारिक सामग्री का रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स (आरएसजीसी), श्रीनगर में अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने मैराथन के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए आधिकारिक प्रचार वीडियो भी जारी किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई मैराथन कैप, फिनिशर मेडल और रेसिंग किट का अनावरण किया गया। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

यह पहल खेल पर्यटन को बढ़ावा देने, लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति प्रेरित करने तथा जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

कहा, कश्मीर मैराथन को देश के प्रमुख मैराथन आयोजनों में शामिल कर खेल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैराथन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को नई दिशा देने की सरकार की व्यापक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, मैराथन अपने आप में एक बड़ा आयोजन है। हम जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। पर्यटन केवल डेस्टिनेशन वेडिंग या सम्मेलन तक सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध स्कीइंग, गोंडोला, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, मछली पकड़ने और अन्य साहसिक गतिविधियों जैसे अनूठे अनुभवों को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले।卐

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कश्मीर मैराथन को दिल्ली, मुंबई, लद्दाख और देश के अन्य प्रतिष्ठित मैराथन आयोजनों की तर्ज पर विकसित किया जाए।

उन्होंने कहा, 卐मैंने दिल्ली, मुंबई और देश के कई राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मैराथन देखी हैं। आज लद्दाख मैराथन में देश और दुनिया भर से धावक भाग लेते हैं। हमारी इच्छा है कि कश्मीर मैराथन और जम्मू हाफ मैराथन भी उसी स्तर की पहचान और प्रतिष्ठा हासिल करें।

कश्मीर घाटी में ट्रैक अनुरक्षण कार्य के कारण 11 जुलाई से 25 जुलाई तक कुछ ट्रेनें रद्द

जम्मू, 10 जुलाई। यात्रियों की सुरक्षा और रेल संचालन को बेहतर बनाने के लिए जम्मू मंडल द्वारा कश्मीर घाटी के *बनिहाल - बारामूला रेल खंड* पर ट्रैक अनुरक्षण का कार्य कराया जा रहा है। गर्मी के मौसम में ट्रैक को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए यह कार्य जरूरी है।

इस कार्य को आसानी से पूरा करने के लिए *11 जुलाई 2026 से 25 जुलाई 2026 तक* इस रूट पर ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। इस दौरान कश्मीर घाटी में चलने वाली 3 ट्रेनें रद्द रहेंगी।

रद्द की जाने वाली ट्रेनें हैं-

गाड़ी संख्या 74615 बनिहाल - बारामूला*, गाड़ी संख्या 74632 बारामूला - बडगाम* और *गाड़ी संख्या 74628 बडगाम - बनिहाल*। ये सभी

ट्रेनें 11 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक नहीं चलेंगी।

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी *IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप या रेल मदद 139 पर जरूर चेक कर लें। असुविधा के लिए रेलवे खेद व्यक्त करता है और यात्रियों से सहयोग की अपील करता है।

साभार : अशोक कुमार मुनड़ेतिया

प्राथमिकता के आधार पर तैयार करें अपनी कार्य-सूची

आज आप जितना कर सकती हैं, उससे अधिक करने की कोशिश न करें। अपनी गतिविधियों की छंटनी शुरू कर दीजिए और फिर अपनी कार्य-सूची पर पुनर्विचार कीजिए। जो चीजें बेकार एवं महत्वहीन हैं, उन्हें बाहर कर दीजिए। आप जो भी कर सकती हैं या करना चाहती हैं, उन तमाम चीजों को एक ही दिन में करने का प्रयास न करें। सबसे जरूरी चीज पर नजर रखें एवं प्राथमिकता के आधार पर उन्हें करें। व्यक्तिगत रिश्ते बनाएं, ताकि काम एवं जीवन में सहजता आए।

एक समय में एक ही काम

अपना समय केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करें, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। दो या उससे अधिक काम एक साथ करने से तौबा करें, तब भी जब चीजें आसान लगती हों या लगता हो कि आप कर लेंगी। जब आप एक से अधिक काम एक ही बार में करती हैं तो आपका ध्यान बंट जाता है। आप एकाग्रता खो देती हैं, जो कि बेहतर प्रदर्शन के लिए जरूरी है।

कुछ उदाहरण

यदि आप एक साथ खाती एवं पढ़ती हैं तो आपका कुछ ध्यान पढ़ने पर और कुछ खाने पर होता है। आप कोई भी चीज ढंग से नहीं कर पाती हैं। जब आप टहलती हैं तो टहलें, जब आप बैठती हैं तो बैठें। भटकें नहीं। जब ड्राइव करें तो पूरा ध्यान रोप पर रखें। काफी ऊंची आवाज में संगीत सुनना या चालक एवं यात्री के बीच की बातचीत कई सड़क हादसों का कारण होती है। यदि आप यात्री हैं तो चालक को गाड़ी चलानें दें न कि उससे बातचीत करें।

पांच गुण होना महत्वपूर्ण

किसी भी स्त्री या पुरुष में पांच गुण होना चाहिए। वे हैं–शिष्टाचार, उदारता, लगन, संकल्प एवं दया भाव। शिष्टाचार से आप बेइज्जती को अनदेखा कर सकती हैं, उदारता से सबको जीत सकती हैं। लगन से लोग आप पर विश्वास करेंगे और संकल्प एवं दया भाव से सफलता प्राप्त कर सकती हैं।अच्छी संगत, अच्छी किताबें एवं प्रार्थना– ये तीन चीजें किसी मनुष्य को तीनों लोकों का सम्राट बनाती हैं।

सफलता नैसर्गिक नहीं होती

सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया नैसर्गिक नहीं है। सफलता हमें विरासत में नहीं मिलती। इसे हम अपने प्रयासों से पैदा करते हैं। यह हमारे कठिन परिश्रम एवं क्रियाओं की पुनरावृत्ति का काल होता है। संघर्ष जीवन है और जीवन की क्रियाएं ही इसे कर सकती हैं। हमें केवल सपने देखने वाला नहीं बल्कि आगे बढ़कर उसे करने वाला बनना चाहिए।

सेमिनारों में कुछ नहीं

हम समय–समय पर प्रेरित करने वाले लोगों से मिलते रहते हैं या सेमिनारों में ऐसे भाषण सुनते रहते हैं। इस प्रकार के पारस्परिक क्रिया से हमें अपने तरीकों को सुधारने एवं काम करने की शैली की और बेहतर करने के उपाय मिलते हैं। हम उनको अपनाते हैं और महसूस करते हैं कि अपने आप को और बेहतर करें एवं जीवन में बदलाव लाने का रहस्य पा लिया है। यह पूरी गहमागहमी दो–चार दिनों में खत्म हो जाती है और हम फिर वहीं होते हैं जहां हम थे।

ऊर्जा, समय व पैसे बचायें

याद रखिये सेमिनार एवं कार्यशाला में भाग लेना समय, ऊर्जा और पैसे की बर्बादी है, यदि हम उन चीजों को नहीं अपनाते, जो वे हम तक पहुंचाना चाहते हैं। यदि आपको कोई बेहतरीन आइडिया मिलता है तो आप अपने आप से पूछिए कि आप इससे क्या करने जा रहे हैं और आप इसे कैसे करेंगे। सभी बातों को लिखिए और फिर निर्णय लीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। किन उपायों को लागू करना है, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सब कुछ करने के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए।

अच्छा दिखने के लिए मेकअप कर के घर से बाहर निकलना अब जरूरत सा बन गया है, लेकिन मेकअप के सभी उत्पाद आपके लिए अच्छे हो ये कतई जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे उत्पाद भी है जो आपको कुछ समय तक सुंदर तो दिखा देते है लेकिन आपकी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते है। आइए, जानते हैं ऐसी ही 5 मेकअप सामग्री के बारे में जिनका इस्तेमाल आपको कम से कम ही करना चाहिए

इन मेकअप प्रोडक्ट्स से रहें दूर

टेलकम पाउडर

टेलकम पाउडर सामान्य तौर पर आपमें से कई लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा होगा। भले ही आप इसे सुरक्षित मानते हों, लेकिन इसमें मौजूद सिलेकेट्स नामक तत्व आपको एलर्जी, फेफड़ों में इंफेक्शन या फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार बना सकता है।

ब्लीच क्रीम

अधिकांश ब्लीच क्रीम में पाया जाने वाला हाइड्रोक्विनोन त्वचा के निकलने, लालिमा या लाल रेशेस अथवा त्वचा के रूखेपन के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी जगह त्वचा प्रभावशाली घरेलू उत्पादों का प्रयोग करना बेहतर होगा।

लिप ग्लॉस

होंठों पर चमकदार नमी लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला लिपग्लॉस कुछ ऐसे केमिकल्स से युक्त होता है, जो आपके होंठों की त्वचा को अंदर से रूखा कर सकते हैं साथ ही रोमछिद्रों को ब्लॉक कर सकते हैं।

हेयर कलर

इसमें मौजूद हानिकारक केमिकल्स आपके सिर की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा त्वचा का लाल होना और खुजली जैसी समस्याएं भी हो सकती है जो अन्य गंभीर समस्याओं को जन्म देती हैं।

नेल पॉलिश

भले ही अपको रंगीन, चमकीले नेल पॉलिश का शौक हो, लेकिन इनमें मौजूद एसीटोन आपके नाखूनों को दाग या धब्बों से युक्त बनाने के साथ ही कमजोर बनाने में सहायक होता है। इसके लिए हमेशा नेल पॉलिश का इस्तेमाल करने से बचें।

अक्सर महिलाओं की ये समस्या होती है कि घर का खर्च ज्यादा हो रहा है और पैसों से जुड़ी बचत नहीं हो पा रही है। यहां निवेश और बचत की नहीं खर्च की बात हो रही है। घरों में आजकल की व्यस्त लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि उनका इतना खर्च आखिर कैसे बढ़ गया है। ये सब कुछ पैसे से जुड़ी कुछ गलतियों के कारण होता है।

पैसे के बारे में बात नहीं करना

आम तौर पर यही देखा जाता है कि पति और पत्नी एक दूसरे से इसके बारे में बात नहीं करते। पत्नी घर संभाल रही हो या फिर बाहर काम कर रही हो तो भी इसके बारे में बातें नहीं की जातीं। बच्चे अगर पढ़ने की उम्र में हैं या टीनएज हो गए हैं तो उन्हें भी अक्सर घर पर ये नहीं बताया जाता है कि निवेश और बचत की जरूरत क्या है। हफ्ते में कम से कम एक बार सभी को बैठकर घर और पैसे के खर्च से जुड़ी बातें करनी चाहिए। इससे वो खर्च भी सामने आ जाता है जिसका शायद अंदाजा भी नहीं होता। ये घर का बजट बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है।

पहले खर्च फिर जो बचा वो निवेश

हमारी भारतीय संस्कृति में एक आम कहावत है कि , 'जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो'। ये बहुत अच्छा कथन है, लेकिन इसे हमें थोड़ा सा बदलना होगा क्योंकि हम हमेशा जितना खर्च है उतना कर लो और उसके बाद जो बचा वो बचत। इससे समस्या ये होती है कि जरूरत से अधिक खर्च भी हो जाता है और बचत कम रह जाती है। इसे थोड़ा सा बदलने की जरूरत है और कमाई के बाद एक निश्चित बचत और उसके बाद जितना बचा उसे खर्च करना चाहिए। ये बजट आसानी से बन सकता है कि महीने में कितनी बचत की जा सकती है।

बचत और निवेश का अंतर न समझना

मान लीजिए आप हर महीने की आय में से कुछ पैसे बचा लेते हैं, लेकिन क्या इन पैसों को बचाने से सिर्फ काम हो जाता है? जी नहीं, बचत और निवेश में काफी अंतर है जिसे समझने की जरूरत है। पैसे ड्रॉअर में पड़े रहें या फिर वो बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखा है तो उससे हमारे भविष्य के लिए कोई फायदा हो रहा है? बिलकुल नहीं। तन्वी जी का कहना है कि उनके पास बहुत से लोग आते हैं और वो यहीं मात खा जाते हैं। उन्हें निवेश इस बारे में सोचकर करना चाहिए कि भविष्य में ये कितना रिटर्न देगा।

बार-बार बिगड़ जाता है घर का बजट तो ना करें पैसों से जुड़ी ये गलतियां

अपनी बचत और निवेश को ऑटोमैटिक मोड पर नहीं डालना

बैंक की आरडी या एफडी जिसका ऑटोमैटिक पैसा कटता है वो ज्यादा सही है। भले ही बचत और निवेश का कोई भी मोड हो पैसा ऑटोमैटिक हर महीने कटना चाहिए। कारण ये है कि अगर बचत हर वक्त नहीं होगी तो हम उस कमाई को खर्च करने के लिए उत्सुक रहेंगे। अकाउंट में या जेब में ज्यादा पैसा होने का मतलब है कि उसे खर्च करने का लालच भी बढ़ जाएगा। अगर सैलरी आते ही एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से पैसे निवेश कर देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा।

अपने पैसे को अलग–अलग जगह न निवेश करना

पैसा है आपके पास तो क्या हर बार वो एक ही तरह से निवेश किया जाएगा? कई लोग सिर्फ FD बनाते रहते हैं, कुछ को पोस्ट ऑफिस की NSC अच्छी लगती है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि पैसे के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। कारण ये है कि अगर एक ही तरह से पैसा निवेश होगा तो खतरे की स्थिति में एक ही साथ उसके खर्च होने या फिर डूब जाने की गुंजाइश भी होती है।

फाइनेंशियल भाषा से डरना और रिस्क न लेना

इंसान का दिमाग जो चीज समझ नहीं पाता वो उससे हमेशा डरता रहता है और ये बहुत आम घटना है कि लोग खुद को फाइनेंशियल भाषा सिखा नहीं पाते। ऐसे में उन्हें जानकारी न के बराबर रहती है। होता ये है कि ऐसी स्थिति में निवेश के समय हम बहुत ज्यादा सोच विचार में लग जाते हैं और कई बार डर के कारण रिस्क नहीं ले पाते। इससे बाद में नुकसान होने की गुंजाइश है।

कर्ज को न समझना

बहुत से लोगों के पास होम लोन होता है, कार का लोन होता है, क्रेडिट कार्ड से खर्च होता है। अर्थव्यवस्था में कर्ज की दरें लगातार बढ़ती और घटती रहती है। ऐसे में हमारे कर्ज पर भी असर पड़ता है। किसी भी तरह के लोन को हमेशा फाइनेंशियल एक्सपर्ट से हर साल रिव्यू करवाना चाहिए। क्या पता ब्याज की दर इससे कम हो सके। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड सबसे महंगा तरीका है ऐसे में कई बार वो बहुत महंगा पड़ जाता है। कोशिश करें कि हर वक्त क्रेडिट कार्ड निकालने से बचें।

क्या आपके वार्डरोब में है जींस के ये ट्रैंडी कलेक्शन

जींस एक ऐसी कॉमन ड्रैस है, जो हर लड़की के वार्डरोब में जरूर मौजूद होती है। बाजार में कई स्टाइलिश जींस आ चुकी हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद और फिटिंग के मुताबिक खरीद सकती हैं। जींस खरीदने से पहले आपको यह जानना जरूरी हैं कि आजकल किस पैटर्न की जींस का चलन ज्यादा है। आज हम आपको जींस की इन्हीं वैरायटी के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपको अपनी पसंद की जींस खरीदने में आसानी होगी.

रिप्ड जींस

रिप्ड जींस एक दशक से फैशन ट्रैंड में बनी हुई है। कॉमन यंग गर्ल्स से लेकर बॉलीवुड एक्ट्रैस सभी में इसका क्रेज है। शायद ही कोई लड़की होगी जिसके वार्डरोब में रिप्ड जींस न हो। एक दशक पहले ट्रैंड में आई ये जींस आज भी लड़कियों की पहली पसंद बनी हुई है। इसमें जींस के कई हिस्से में कुछ स्लिट्स या कट्स बने होते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इसे फटी जींस भी कहते हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी जींस है, जिसे आप नहीं पहनतीं तो उसे ब्लेड से कट करके रिप्ड जींस का लुक दें सकती हैं। रिप्ड जींस को आप लॉन्ग कुर्ती या फिर किसी भी टॉप के साथ वियर कर सकती हैं। ये आपको कूल और स्टाइलिश लुक देगी।

बैगी जींस

बैगी जींस अपने लूज साइज की वजह से काफी कंफर्टेबल होती है। दो से तीन दशक पहले इस पैटर्न की जींस का काफी चलन था। एक बार फिर से इसका ट्रैंड लौट आया है। यही वजह है कि सैलेब्स में भी ये जींस काफी पॉपुलर है। ट्रैवलिंग के दौरान या कहीं आने–जाने के लिए एक्ट्रैस इसे कैरी किए नजर आती रही हैं।

पैच वर्क जींस

इन दिनों पैच वर्क जींस भी काफी पॉपुलर हैं। यंग गर्ल्स से लेकर सैलेब्स इसे पहने नजर आती रहती हैं। ये जींस अलग–अलग रंग के जींस के चौकोर टुकड़ों को एक साथ पैच करके बनाई जाती है, जो देखने में काफी युनीक और कूल लगती हैं।

बेल बॉटम जींस

पुराने जमाने में आपने हीरो–हीरोइन को फिल्मों में नीचे से खुली पैंट या जींस पहने देखा होगा। इस स्टाइल को बेल बॉटम स्टाइल कहते हैं। आजकल बेल बॉटम जींस का फैशन फिर से लौट आया है। ये जींस काफी कंफर्टेबल होती हैं। यंग गर्ल्स से लेकर वर्किंग वुमन बेल बॉटम जींस पहनना पसंद कर रही हैं।

स्किन फिट जींस

इसके नाम से ही क्लियर है कि ये जींस कैसी होगा। ये पूरी तरह स्किन टाइट होती है। ज्यादातर लड़कियां स्किन फिट जींस पहनना पसंद करती हैं, लेकिन अगर कंफर्ट की बात करें तो ये उतनी आरामदायक नहीं होती। तब भी इस जींस का क्रेज लड़कियों में बना हुआ है। इसे आप अपनी मनपसंद कुर्ती या फिर टॉप के साथ कैरी कर सकती हैं।

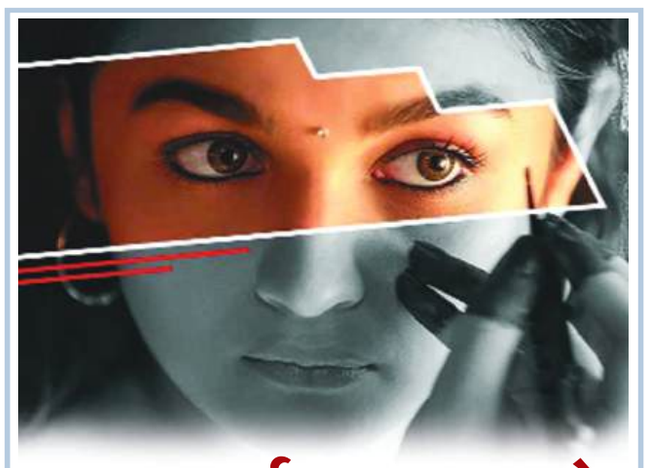

कलर आईलाइनर लगाने से पहले जरूरी टिप्स मिलेगा स्टाइलिश लुक

चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लड़कियां मेकअप करना पसंद करती है। वहीं आंखों को बड़ा, आकर्षित दिखाने के लिए आईलाइनर लगाती है। बात अगर आईलाइनर की करें तो आमतौर पर लड़कियां इसमें ब्लैक कलर पसंद करती है। मगर आजकल लड़कियों में कलरफुल आईलाइनर का क्रेज भी बढ़ रहा है। इससे लुक और भी स्टाइलिश नजर आता है। मगर इसे लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान देने की जरूरत होती है। कलर आईलाइनर लगाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

मेकअप ना करें

कलर आईलाइनर अक्सर आंखों को हाइलाइट करने के लिए लगाया जाता है। इसलिए इसे लगाने के बाद अपना रेगुलर मेकअप ना करें। नहीं तो इससे आपका मेकअप अधिक लगेगा।

सही कलर चुनें

अगर आप पहली बार कलर आईलाइनर लगाने वाली है तो इसके लिए रंग चुनें। इसके लिए आप पिंक, लैवेंडर, बैंगनी, सुनहरा या अपनी ड्रेस से मैचिंग रंग चुन सकती है।

आंखों पर ध्यान दें

कलर आईलाइनर लगाने के लिए बस अपनी आंखों पर फोकस करें। इसके साथ हैवी व बोल्ड मेकअप करने की गलती ना करें। ऐसा करने से आपकी आंखों पर ध्यान नहीं जाएगा।

डार्क कलर अप्लाई करें

अगर आप पहली बार आईलाइनर लगाने वाली है तो इसके लिए डार्क कलर यूज करें। असल में, इससे आपका लुक एकदम बदल जाएगा। ऐसे में आप पहली बार के लिए ब्राउन या ब्लू कलर चुन सकती है। मस्कारा ब्लैक कलर का लगाएं आप भले ही आईलाइनर कलर्ड चुन रही है मगर इसके साथ मस्कारा ब्लैक ही लगाएं। इससे आपकी आंखों को ग्रेसफुल लुक मिलेगा। इसके साथ ही फेक आईलैशेज लगाने की गलती ना करें।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबर:- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

जेकेपीसीसी किसान कांग्रेस ने कृषि निदेशक को सौंपा ज्ञापन

जम्मू, 10 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भारत प्रिये ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को कृषि निदेशक जम्मू अनिल गुप्ता से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं, मांगों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के दौरान भारत प्रिये ने कृषि विभाग से किसानों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत बनाने तथा जम्मू जिले के किसानों को आ रही व्यावहारिक समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनकी वास्तविक समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। बैठक में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी), कैपेक्स, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) तथा नाबार्ड वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत जम्मू जिले में चल रहे विकास कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने कृषि अवसंरचना परियोजनाओं, सिंचाई सुविधाओं, कृषि मशीनीकरण, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने वाली विभिन्न पहलों की प्रगति की जानकारी ली। जेकेपीसीसी किसान कांग्रेस ने स्वीकृत निधियों के पारदर्शी उपयोग, विकास कार्यों की नियमित निगरानी तथा योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक समय पर पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही कृषि नीतियों और योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के दौरान किसानों के प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद बनाए रखने की भी मांग की। कृषि निदेशक जम्मू अनिल गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत हुई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग कृषि अवसंरचना को मजबूत बनाने, सेवाओं में सुधार लाने तथा सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किसान हितैषी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

सिविल डिफेंस का जागरूकता शिविर- अनाथ बच्चों को प्राथमिक उपचार, सीपीआर और आपदा प्रबंधन की दी गई जानकारी

जम्मू, 10 जुलाई (हि.स.)। सिविल डिफेंस जम्मू द्वारा शुक्रवार को अम्फल्ला स्थित वेद मंदिर बाल निकेतन में एक दिवसीय सिविल डिफेंस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अनाथ बच्चों के लिए संचालित इस संस्थान में आयोजित कार्यक्रम की निगरानी डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस जम्मू एवं डीवाईएसपी तजिंदर कौर ने की। कार्यक्रम का समन्वय मुख्य वार्डन परमजीत कुमार और उप मुख्य वार्डन आर. विजय मगोत्रा ने किया। शिविर में संस्थान के लगभग 100 अनाथ बच्चों और स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड), अग्निशमन, सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) तथा आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले विभिन्न जीवनरक्षक उपायों की जानकारी दी गई।

सिविल डिफेंस की टीम ने इन तकनीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया जिससे प्रतिभागियों को आपदा के समय त्वरित और सही प्रतिक्रिया देने का प्रशिक्षण मिल सके। कार्यक्रम में वेद मंदिर बाल निकेतन के सचिव नगर मल गुप्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने सिविल डिफेंस जम्मू की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम बच्चों और संस्थान के कर्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इस अवसर पर मुख्य वार्डन परमजीत कुमार और उप मुख्य वार्डन आर. विजय मगोत्रा ने व्याख्यान देते हुए प्राकृतिक आपदाओं, आगजनी, औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा अन्य आपात स्थितियों के दौरान सिविल डिफेंस वार्डनों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सिविल डिफेंस के प्रशिक्षित स्वयंसेवक संकट की घड़ी में प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले कर्मियों के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम योगदान देते हैं।

14 जुलाई को मनाई जाएगी आषाढ़ अमावस्या, पितृ तर्पण व दान-पुण्य का रहेगा विशेष महत्व

जम्मू, 10 जुलाई (हि.स.)। आषाढ़ अमावस्या इस वर्ष 14 जुलाई को मनाई जाएगी। इस अवसर पर पितृ तर्पण, श्राद्ध, दान-पुण्य और स्नान का विशेष धार्मिक महत्व रहेगा। कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट जम्मू के अध्यक्ष एवं ज्योतिषाचार्य महंत रोहित शास्त्री ने बताया कि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने जाते हैं और इस दिन पितरों के निमित्त किए गए तर्पण, श्राद्ध तथा दान-पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 13 जुलाई की शाम 6:50 बजे प्रारंभ होगी और 14 जुलाई को दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी। सूर्योदय व्यापिनी तिथि होने के कारण आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई मंगलवार को मनाई जाएगी जिसे भौमवती अमावस्या भी कहा जाता है। महंत रोहित शास्त्री ने कहा कि श्रद्धालु यदि पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को दान दें। उन्होंने बताया कि इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, पीपल वृक्ष की पूजा, काले तिल, जल एवं पुष्प अर्पित करना तथा ? पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है।

सरकार ने तीन जम्मू-कश्मीर खेल सहायक अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों के दिए आदेश

श्रीनगर, 10 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को प्रशासनिक हित में तीन जम्मू-कश्मीर खेल सहायक अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों के आदेश दिए।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश संख्या 1197-जेके(जीएडी) दिनांक 10.07.2026 के अनुसार जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के मुख्य खेल अधिकारी के पद से तबादले के आदेश के तहत मैक्सिमन गोर्की (जेकेएएस) को जम्मू स्थित जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के महाप्रबंधक के पद पर तैनात किया गया है। जम्मू-कश्मीर खेल परिषद में तबादले के आदेश के तहत स्वाति गुप्ता (जूनियर स्केल जेकेएएस) का तबादला कर उनकी सेवाएं आगे की नियुक्ति के लिए राहत एवं पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी) जम्मू-कश्मीर को सौंप दी गई हैं।

जम्मू फिल्म महोत्सव को दुनिया भर से जबरदस्त प्रतिक्रिया

जम्मू, 10 जुलाई (हि.स.)। जम्मू फिल्म महोत्सव के पांचवें संस्करण को दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। 31 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले ही 35 देशों से 180 प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। इन प्रविष्टियों में 130 लघु फिल्में, 35 वृत्तचित्र और 17 फीचर फिल्में शामिल हैं जो दुनिया भर की विविध संस्कृतियों, भाषाओं और सिनेमाई परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। निर्णायक मंडल के प्रमुख कपिल मट्टू ने जम्मू में पत्रकारों से कहा कि इस महीने के अंत में प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि से पहले और भी प्रविष्टियां आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जम्मू फिल्म महोत्सव का पांचवां संस्करण 28-29 सितंबर को जम्मू में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव जम्मू को वैश्विक फिल्म जगत से जोड़ने की अपनी उल्लेखनीय यात्रा जारी रखे हुए है और उत्तर भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में से एक के रूप में उभरा है। मट्टू ने कहा कि 31 जुलाई की अंतिम तिथि से काफी पहले ही 35 देशों से 180 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। वोमेध और कोशुरवुड स्टूडियो द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत इस महोत्सव में भारत और विदेश के फिल्म निर्माताओं, प्रतिनिधियों, कलाकारों और सिनेमा प्रेमियों को एक साथ लाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने में रुचि व्यक्त की है जबकि महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सिंगापुर के कलाकारों के साथ बातचीत चल रही है।

मानसून से बढ़ते खतरे पर कर्नल आरके शर्मा ने जताई चिंता

जम्मू, 10 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही मानसूनी बारिश और बेमौसम वर्षा से हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कर्नल आरके शर्मा ने सरकार से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की ड्रेनेज व्यवस्था में व्यापक सुधार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक आधार पर विकसित ड्रेनेज नेटवर्क के अभाव में हर वर्ष बाढ़, जलभराव और सड़कों, मकानों तथा कृषि भूमि को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

उनका कहना था कि कई नई आवासीय कॉलोनियां बिना पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के विकसित की गई हैं जिसके कारण बारिश के दौरान लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

कर्नल शर्मा ने बनयान एन्क्लेव का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों द्वारा कई बार प्रशासन के समक्ष मामला उठाने और विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद इलाके में समुचित ड्रेनेज व्यवस्था विकसित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हर बार भारी बारिश होने पर वर्षा का पानी घरों में घुस जाता है और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में आई बाढ़ से हुई तबाही को भुलाया नहीं जा सकता और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन को चौबीसों घंटे सतर्क रहकर आवश्यक तैयारियां करनी होंगी। उनका कहना था कि उचित ड्रेनेज योजना के बिना विकास कार्य अधूरे हैं और प्रशासन को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए।

बहु-विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर में 800 से अधिक लोगों को मिला नि-शुल्क उपचार

जम्मू, 10 जुलाई (हि.स.)। सनासर के दुर्गम क्षेत्र में एक विशाल बहु-विशेषज्ञ (मल्टीस्पेशियलिटी) चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 800 से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। पर्यटन विकास प्राधिकरण, जेकेटीडीसी, भारतीय सेना, एसओजी, सिबा इवेंट मैनेजमेंट एंड इनोवेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड तथा सोसायटी फॉर शेड्यूल्ड एंड बैकवर्ड क्लासेज़ के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस शिविर का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना था। सुबह 10 बजे शुरू हुए शिविर में सनासर और आसपास के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कई बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चों वाले परिवार घंटों पैदल कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर चिकित्सा सुविधा लेने पहुंचे। दोपहर 2:30 बजे तक चले इस शिविर में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने सभी मरीजों की जांच कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया। शिविर में जेके मेडिसिटी उजाला सिग्नस अस्पताल और त्रिनेत्रम मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने विभिन्न सामान्य एवं जटिल बीमारियों की जांच और परामर्श दिया। इसके अलावा दंत स्वास्थ्य जांच, आंखों की जांच, आवश्यक दवाइयों और आई ड्रॉप्स का निःशुल्क वितरण भी किया गया।

सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में शोध पद्धति पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित

जम्मू, 10 जुलाई (हि.स.)। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के शिक्षा अध्ययन विभाग द्वारा शिक्षा शास्त्रार्थ फोरम के अंतर्गत रिसर्च में वेरिएबल्स को समझना विषय पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कुलपति प्रो. संजीव जैन के संरक्षण में आयोजित हुआ जिसमें विभाग के संकाय सदस्यों और बड़ी संख्या में शोधार्थियों ने भाग लिया।

व्याख्यान का उद्देश्य शोध पद्धति की समझ को मजबूत करना तथा अकादमिक शोध की गुणवत्ता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की शुरुआत नागालैंड विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षा विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. सीमा रानी थप्पा के स्वागत से हुई। विभागाध्यक्ष प्रो. असित के. मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय शोध के लिए शोध पद्धति की गहन समझ आवश्यक है। उन्होंने बताया कि शोध में विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स की सही पहचान और उनका उचित उपयोग प्रभावी शोध डिज़ाइन की आधारशिला है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा शास्त्रार्थ फोरम के वर्तमान सत्र का यह पहला शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शोध एवं बौद्धिक विमर्श को प्रोत्साहित करना है।

अपने व्याख्यान में डॉ. थप्पा ने शैक्षिक एवं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वेरिएबल्स की अवधारणा, उनकी विशेषताओं तथा महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने स्वतंत्र, आश्रित, मॉडरेटर, मेडिएटर, कंट्रोल तथा एक्स्ट्रेनियस वेरिएबल्स सहित विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स की व्याख्या करते हुए बताया कि इनकी सही पहचान और संचालन से शोध की वैधता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। उन्होंने शोध के उद्देश्यों के अनुरूप वेरिएबल्स के चयन, परिकल्पना निर्माण तथा शोध के दौरान होने वाली सामान्य पद्धतिगत त्रुटियों से बचने के उपाय भी साझा किए। व्याख्यान के बाद आयोजित संवादात्मक सत्र में शोधार्थियों ने गुणात्मक, मात्रात्मक एवं मिश्रित शोध, परिचालनात्मक परिभाषाओं, अवधारणात्मक ढांचे और शोध डिज़ाइन से जुड़े प्रश्न पूछे।

जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर पूर्व मंत्री का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला

जम्मू, 10 जुलाई (हि.स.)। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री बाली भगत ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के प्रदर्शन को लेकर पार्टी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा।उन्होंने आरोप लगाया कि मीरवाइज उमर फारूक को आमंत्रित कर एनसी ने राज्य के दर्जे के संवैधानिक मुद्दे को अलगाववादी राजनीति से जोड़ दिया है। बाली भगत ने कहा कि यदि प्रदर्शन केवल राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए होता तो किसी अलगाववादी नेता को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसी संवैधानिक राजनीति की आड़ में अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही आश्वस्त कर चुके हैं कि उचित समय पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। ऐसे में जंतर-मंतर का प्रदर्शन राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। बाली भगत ने कहा कि राज्य का दर्जा संवैधानिक विषय है और इसे अलगाववादी राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

ओटीटी से सतलुज फिल्म हटाए जाने पर सिख यूनाइटेड फ्रंट ने जताई आपत्ति

जम्मू, 10 जुलाई (हि.स.)। सिख यूनाइटेड फ्रंट जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष एस. सुदर्शन सिंह वजीर ने विभिन्न सिख संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता में जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म को स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध होने के दो दिन बाद ही हटा दिया गया जबकि इसके पीछे किसी सरकारी एजेंसी ने आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है।

वजीर ने कहा कि फिल्म पंजाब के उथल-पुथल भरे दौर के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघनों और अवैध अंतिम संस्कारों की जांच करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि खालड़ा ने हजारों अज्ञात शवों के रिकॉर्ड सामने लाकर इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया था। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित विभिन्न फिल्मों के साथ अलग-अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उनका कहना था कि यदि अन्य समुदायों के दर्द को दिखाने वाली फिल्मों का प्रदर्शन हो सकता है तो पंजाब के दौर और सिखों की पीड़ा को दर्शाने वाली फिल्म को भी दर्शकों तक पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए।

वजीर ने जसवंत सिंह खालड़ा को मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला साहसी व्यक्तित्व बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

सामाजिक सेवा में योगदान देने वाली महिलाओं को किया सम्मानित

जम्मू, 10 जुलाई (हि.स.)। युवा भगत सभा उप-जिला आर.एस. पुरा ने सामाजिक सेवा एवं जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली अपनी महिला सदस्यों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉ. नरेंद्र सिंह न महिलाओं को सम्मानित करते हुए समाजहित में उनके समर्पण और निस्वार्थ सेवा की सराहना की। अपने संबोधन में डॉ. नरेंद्र सिंह ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सामाजिक विकास की आधारशिला है और उनके योगदान को सदैव सम्मान व प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने सम्मानित महिलाओं को भविष्य में भी समाज सेवा के कार्यों को इसी समर्पण के साथ जारी रखने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में युवा भगत सभा के अध्यक्ष डी.के. भगत, प्रधान देव राज भगत, उपाध्यक्ष दिनेश भगत, महासचिव रोमी भगत, सचिव इंदर पाल भगत, सदस्य राहुल भगत सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभा के पदाधिकारियों ने समारोह में शामिल होने पर मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करते हुए समाज सेवा को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

Union Territory of Jammu and Kashmir

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER PMGSY CIRCLE REASI.

SHORT NOTICE INVITING e-TENDERS

e-NIT No:-SE-REASI/PMGSY/31of 2026-27Dated:-09-07-2026

Superintending Engineer PMGSY Circle Reasi on behalf of The LT Government of Jammu & Kashmir (UT), invites e-tenders on %age Above/Excess (+) OR %age Below/ Less (-) basis(i.e. on Percentage-Rate Basis) from approved and eligible Contractors registered with J&K U.T.Govt, CPWD, Railways or equivalent and other State/U.T.Govts up to 1700 Hrs. on16-07-2026 for each of the following works&The Technical Santion is here by accorded by order No:-CEJ/PMGSY/2154 of 2026Dated:-25-06-2026.

S.No.	Name of the Work/Package No.	Name of the PIU	Constt. Part (Rs. In Lacs)	Maintt. Part (Rs. In Lacs)	Total (Rs. In Lacs)	Cost of Documents (Rs. In Lacs)	Bid Security (EMD) @2% of total cost rounded to the nearest thousand (Rs. In Lacs)	Time Allowed for completion	Call of tender	Time and date of opening of technical bids	Class of Contractor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Balance work for Construction of road from "L034 Kundradhan to Mamankot Upper", Package No. JK14-567, Regular PMGSY (Batch-I, 2017-18), Stage-I, Block Mahore, District Reasi, (Length = 27.00 km) **Adv. Cost excluding maintenance but inclusive of GST-Rs.578.80Lac**	Mahore	578.80	-	578.80	0.10	11.57	07 Months	2nd	18-07-2026 1100 Hrs.	Any registered contractor with State/U.T. PWD/CPWD/ Railways or equivalent qualifying eligibility criteria as provided in the Standard Bidding Documents can tender for the works

Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bid should be submitted online on websitewww.pmgsytendersjk.gov.in. The bidder would be required to register on the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have valid Digital Signature Certificate (DSC) from any one of the authorized Certifying Authorities (CA).
"Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in PMGSY may obtain the same from the website: www. pmgsytendersjk.gov.in. Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the valid digital signatures issued from authorized Certifying Authorities (CA)can use the same in this tender.

Date and Time Schedule

S.No	Particulars	Date	Time
1.	Date of issue of tender notice	09-07-2026	1855hrs
2.	Document Download / Sale Start Date	10-07-2026	1855hrs
3.	Pre-Bid Meeting	11-07-2026	1200 hrs
4.	Bid Submission Start Date	11-07-2026	1700 hrs
5.	Bid Submission End Date	16-07-2026	1700 hrs
6.	Date & Time of Opening of Technical Bids	18-07-2026	1100 hrs
7.	Date & Time of Opening of Financial Bids	To be notified after technical evaluation is completed	

A Pre bid meeting will be held on 11-07-2026 at 1200 Hrs. in the Office of The Superintending Engineer PMGSY Circle Reasi to clarify the issues and to answer questions on any matter that may be raised at that stage as stated in Clause 9 of instruction to bidders of the Bidding documents.
The site for the work is available.
Only online submission of bids is permitted, therefore; bids must be submitted online on website www.pmgsytendersjk.gov.in. The technical qualification part of the bids will be opened online at 1100 Hrs. on 18-07-2026 by the authorized officers. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened online on the next working day at the same time.
The date and time of opening of Financial Bids shall be notified on Web Site http://pmgsytendersjk.gov.in. This is conveyed to the bidders automatically through an e-mail message on their e-mail address. The Financial bids shall be opened accordingly on line on same Web Site at the Office of The Superintending Engineer PMGSY Circle Reasi at Room No. 302, Block-2. DC Office Complex, Reasi.
The bidder is not required to quote his rate for routine maintenance. The rates to be paid for routine maintenance are indicated in the Bill of Quantities. Further, the payment for routine maintenance to the contractor shall be regulated based on his performance of maintenance activities.
The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 120 days after the deadline date for bid submission.
Sd/-
No:-SE/PMGSY/R/2026-27/2535-2610
Dated:-09-07-2026

SD/-
Superintending Engineer PMGSY Circle Reasi
For and on behalf of Lt. Government of Jammu and Kashmir

DIP/J-5434/26
Dtd: 10-7-2026

संपादकीय

राही- पर्यटन विकास को नई रफ्तार

जम्मू जैसे शहर में, जहां पूरे वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं, राही- हॉप जम्मू बस सेवा पर्यटकों के लिए एक अत्यंत आवश्यक सुविधा है। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह एक अभिनव पहल है। अमरनाथ यात्रियों को जम्मू के पर्यटन स्थलों का सुविधाजनक और कम खर्च में भ्रमण कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस सेवा का विस्तार अन्य मौसमों, विशेषकर सर्दियों में आने वाले पर्यटकों के लिए भी किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जम्मू घूमने का सबसे पसंदीदा समय माना जाता है।

यह सराहनीय है कि जिला प्रशासन जम्मू ने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से राही- हॉप जम्मू बस सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। अब पर्यटक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं।

इस सेवा की परिकल्पना और योजना बनाने वालों ने बस मार्गों और उनके नामों का चयन सोच-समझकर किया है। जानकारी के अनुसार, हॉप-ऑन हॉप-ऑफ सेवा चार विशेष मार्गों— तीर्थ लाइन, चिनाब लाइन, सरहद लाइन और फन लाइन— पर संचालित की जाएगी, ताकि पर्यटक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कर सकें।

तीर्थ लाइन (200 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) तवी रिवर फ्रंट से शुरू होकर बहु किला, बावे वाली माता मंदिर, बाग-ए-बहू, मोह माया मंदिर, तिरुपति मंदिर, अमर महल, रणबीरेश्वर मंदिर और रघुनाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी।

चिनाब लाइन (250 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) अखनूर किला, जिया पोता घाट, पांडव गुफा, गुरुद्वारा तपो स्थान संत बाबा सुंदर सिंह जी, कामेश्वर मंदिर और अम्बारन जैसे स्थलों तक जाएगी।

सरहद लाइन (250 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) सुचेतगढ़ सीमा, ऑक्ट्रॉय पोस्ट, रणबीर सिंह पुरा हेरिटेज रेलवे स्टेशन और घराना वेटलैंड का भ्रमण कराएगी।

फन लाइन (200 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) बहु किला, बाग-ए-बहू, एक्वेरियम, बावे वाली माता मंदिर, अमर महल और जम्बू चिड़ियाघर को जोड़ेगी।

सभी बसें तवी रिवर फ्रंट से निर्धारित समयानुसार पूरे दिन संचालित होंगी, जो चारों मार्गों का केंद्रीय बोर्डिंग और प्रस्थान केंद्र होगा।

यह सेवा पर्यटकों को जम्मू के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराने में भी सहायक होगी। अक्सर पर्यटक स्वयं इन स्थानों पर जाते हैं, लेकिन वहां के इतिहास और महत्व से अनजान रह जाते हैं। ऐसे में यह पहल उनके अनुभव को और समृद्ध बनाएगी।

यदि यह बस सेवा सफल रहती है, तो संबंधित अधिकारियों को मनसर, सुरिनसर, पटनीटॉप तथा अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए भी इसी प्रकार की सेवाएं शुरू करनी चाहिए। इससे पर्यटकों को आरामदायक, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प विक्रेताओं, पारंपरिक खाद्य उत्पादों के प्रदाताओं तथा अन्य हितधारकों को भी पर्यटन से जोड़कर उन्हें बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे पर्यटकों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी और क्षेत्र में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।

महिला आरक्षण, लोकसभा सीटों का विस्तार और लोकतंत्र की कसौटी

डॉ. प्रियंका सौरभ

भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी समावेशी भावना है। यह व्यवस्था केवल शासन चलाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का संवैधानिक वादा भी है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी इसी वादे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम रही है। इसलिए

यह चुनौती केवल महिला आरक्षण की नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की समग्र संरचना की है। जब तक राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर नहीं देंगे, तब तक केवल संवैधानिक आरक्षण से अपेक्षित परिवर्तन सीमित रह सकता है। वास्तविक महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल संसद तक पहुँचाना नहीं, बल्कि निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति देना भी है। एक और महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना से जुड़ा है। लगभग सभी दल महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन टिकट वितरण, संगठनात्मक पदों और शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित दिखाई देती है।

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार स्वाभाविक रूप से स्वागत योग्य माना जाता है। यह केवल लैंगिक समानता का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी प्रश्न है। लेकिन महिला आरक्षण की इस ऐतिहासिक पहल के साथ एक नई बहस भी जन्म ले चुकी है। क्या महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा की कुल सीटों में भारी वृद्धि आवश्यक है? क्या मौजूदा 543 सीटों के भीतर ही यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती? यह प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक, प्रशासनिक और संवैधानिक दृष्टि से भी गंभीर है।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों की संभावित वृद्धि दो अलग-अलग विषय हैं। महिला आरक्षण का संबंध निर्वाचित सीटों के आरक्षण से है, जबकि लोकसभा की सीटों का विस्तार भविष्य के परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जुड़ा हुआ विषय है। फिर भी आम नागरिक के मन में यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि यदि आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है, तो क्या इसके लिए संसद का आकार बढ़ाना अनिवार्य है? लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल अधिक सांसद होना नहीं है। लोकतंत्र की सफलता इस बात से मापी जाती है कि जन प्रतिनिधि कितने उत्तरदायी हैं, संसद में कितनी गंभीर बहस होती है, कानून कितनी गुणवत्ता से बनते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान कितना प्रभावी ढंग से होता है। यदि केवल संख्या बढ़ाने से लोकतंत्र मजबूत होता, तो दुनिया के सबसे बड़े संसद वाले देश स्वतः सबसे बेहतर लोकतंत्र भी होते। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है।

देश में आज भी लाखों लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, कृषि संकट और आधारभूत सुविधाओं जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में यदि संसद की संख्या बढ़ती है, तो जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या इससे शासन अधिक प्रभावी होगा या केवल सरकारी खर्च बढ़ेगा? प्रत्येक सांसद के साथ वेतन, कार्यालय, कर्मचारी, आवास, यात्रा, सुरक्षा, संसदीय संसाधन और प्रशासनिक ढांचे का विस्तार भी जुड़ा होता है।

इसलिए सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि वित्तीय निर्णय भी है। हालांकि इस विषय पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अकसर सार्वजनिक चर्चा में सांसदों के वेतन और सरकारी खर्च के बारे में कई दावे किए जाते हैं, जिनके वास्तविक आंकड़े अलग हो सकते हैं।

इसलिए किसी भी आर्थिक तर्क को प्रमाणित सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक विमर्श तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, अतिशयोक्ति पर नहीं।

महिला आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि बिना संवैधानिक गारंटी के राजनीतिक दल महिलाओं को पर्याप्त टिकट नहीं देंगे। पिछले सात दशकों का अनुभव भी यही बताता है कि अधिकांश दल चुनावों में महिलाओं को सीमित अवसर देते रहे हैं। इसलिए आरक्षण आवश्यक है। यह तर्क मजबूत और ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। दूसरी ओर एक चिंता यह भी व्यक्त की जाती है कि क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में समाज के अंतिम पायदान की महिलाओं तक पहुंचेगा? भारतीय राजनीति में चुनाव लड़ना आज भी अत्यधिक संसाधन-आधारित प्रक्रिया है। ऐसे में संभावना रहती है कि टिकट वितरण में राजनीतिक परिवारों, प्रभावशाली नेताओं, आर्थिक रूप से सक्षम उम्मीदवारों अथवा पहले से प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्राथमिकता मिले। यदि ऐसा होता है, तो ग्रामीण, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ पाएगा।

यह चुनौती केवल महिला आरक्षण की नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की समग्र संरचना की है। जब तक राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर नहीं देंगे, तब तक केवल संवैधानिक आरक्षण से अपेक्षित परिवर्तन सीमित रह सकता है।

वास्तविक महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल संसद तक पहुँचाना नहीं, बल्कि निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति देना भी है। एक और महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना से जुड़ा है। लगभग सभी दल महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन टिकट वितरण, संगठनात्मक पदों और शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित दिखाई देती है। यदि राजनीतिक दल स्वयं अपनी कार्यप्रणाली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएँ, तो लोकतांत्रिक संस्कृति अधिक मजबूत होगी।लोकसभा की सीटों में संभावित वृद्धि का एक दूसरा आयाम संघीय संतुलन भी है। परिसीमन के बाद जनसंख्या के आधार पर राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन हो सकता है। इससे विभिन्न राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति का संतुलन प्रभावित होने की संभावना पर भी विशेषज्ञ चर्चा करते रहे हैं। इसलिए यह केवल संसद की संख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि भारतीय संघीय व्यवस्था का भी विषय है। ऐसे निर्णय व्यापक राष्ट्रीय सहमति और गंभीर विमर्श के आधार पर ही लिए जाने चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की एक और चुनौती है—जन प्रतिनिधियों के प्रति जनता का घटता विश्वास। संसद में व्यवधान, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, विधेयकों पर सीमित चर्चा और चुनावी राजनीति का बढ़ता प्रभाव लोगों के मन में यह प्रश्न पैदा करता है कि क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी सर्वोत्तम क्षमता से काम कर रही हैं? यदि जनता पहले से ही प्रतिनिधियों की जवाबदेही पर प्रश्न उठा रही है, तो संख्या बढ़ाने से पहले जवाबदेही बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

लोकतंत्र में गुणवत्ता, संख्या से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि संसद की कार्यवाही अधिक प्रभावी हो, संसदीय समितियाँ बेहतर ढंग से काम करें, सांसद अपने क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहें और कानून निर्माण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बने, तो जनता का विश्वास स्वतः बढ़ेगा। केवल अधिक सांसद होने से लोकतंत्र अधिक उत्तरदायी नहीं हो जाता। महिला आरक्षण को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी आवश्यक है।

महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने से संसद में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सुरक्षा, बाल अधिकार, सामाजिक न्याय और परिवार से जुड़े विषयों पर अधिक संवेदनशील बहस होने की संभावना रहती है। विश्व के अनेक देशों के अनुभव बताते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीति-निर्माण में विविध दृष्टिकोण शामिल होते हैं। इसलिए महिला प्रतिनिधित्व का विस्तार लोकतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है।

लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक न रहे। महिलाओं को केवल चुनाव लड़ने का अवसर ही नहीं, बल्कि संसदीय समितियों, मंत्री परिषदों, नीति आयोगों और राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व में भी समान अवसर मिलें। तभी आरक्षण अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। यदि वर्तमान 543 सीटों के भीतर 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो यह विकल्प भी गंभीर चर्चा का विषय होना चाहिए। इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च की आवश्यकता भी कम होगी। वहीं यदि भविष्य में परिसीमन के संवैधानिक प्रावधानों के कारण सीटों की संख्या बढ़ती है, तो उसके औचित्य, आर्थिक प्रभाव और लोकतांत्रिक लाभों पर भी सरकार को स्पष्ट और पारदर्शी संवाद करना चाहिए।

लोकतंत्र में असहमति विरोध नहीं होती, बल्कि नीति निर्माण को बेहतर बनाने का माध्यम होती है। महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए भी उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी प्रकार सीटों की संभावित वृद्धि का समर्थन या विरोध भी तथ्यों, संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक हित के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक आग्रहों के आधार पर। अंततः भारत को ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता है जहां प्रतिनिधित्व भी बढ़े, जवाबदेही भी मजबूत हो और सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित हो। महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को समृद्ध बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि लोकतांत्रिक सुधार जनता के विश्वास, आर्थिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों को साथ लेकर आगे बढ़ें।

महिला आरक्षण का उद्देश्य अधिकार देना है, न कि केवल संख्या बढ़ाना। यदि यह उद्देश्य मौजूदा व्यवस्था के भीतर अधिक प्रभावी ढंग से पूरा हो सकता है, तो उस विकल्प पर गंभीर विचार होना चाहिए। और यदि सीटों की संख्या बढ़ाना अपरिहार्य हो, तो उसके पीछे के कारण, लाभ और वित्तीय प्रभाव जनता के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ रखे जाने चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार जनता का विश्वास है, और यह विश्वास तभी मजबूत होता है जब निर्णय संवाद, तर्क और उत्तरदायित्व के साथ लिए जाएं।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

भारत ने ब्रिटेन से वाहन आयात पर एफटीए के तहत शुल्क कोटा लाभ लेने की प्रक्रिया को अधिसूचित किया

नई दिल्ली, 10 जुलाई। भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत रियायती सीमा शुल्क पर वाहनों के आयात का रास्ता साफ करते हुए कोटा आधारित शुल्क रियायत का लाभ लेने के लिए आयातकों की मंजूरी प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है। यह व्यवस्था 15 जुलाई, 2026 से लागू होगी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 9 जुलाई को जारी सार्वजनिक सूचना में कहा, '' भारत-ब्रिटेन (सीईटीए) के तहत कोटा आधारित शुल्क दर (टीआरक्यू) के आवंटन की प्रक्रिया अधिसूचित की जाती है।'' इस अधिसूचना के मुताबिक आयातित खेप की सीमा शुल्क निकासी के समय भारत में आयातक को ब्रिटेन के संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन) प्रस्तुत करना होगा।

डीजीएफटी की अधिसूचना के मुताबिक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत भारत दोनों पक्षों के लिए निर्धारित कोटा के साथ मोटर वाहन आयात पर शुल्क को लगभग 110 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करेगा। भारत इस व्यापार समझौते के लागू होने के पहले 15 वर्ष के दौरान ब्रिटेन से पारंपरिक इंजन वाले यात्री वाहनों की 3.78 लाख इकाइयों के आयात की रियायती सीमा शुल्क पर अनुमति देगा।

अधिसूचना के मुताबिक डीजीएफटी ने कहा, '' केवल ब्रिटेन में विनिर्मित वाहनों के मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) अथवा उनके विधिवत अधिकृत डीलर/चैनल पार्टनर ही टीआरक्यू के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।'' व्यापार महानिदेशालय ने यह भी कहा कि पात्रता के लिए प्रत्येक आवेदक को ब्रिटेन स्थित वाहन विनिर्माता (ओईएम) द्वारा जारी पूर्व-क्रय समझौता प्रस्तुत करना होगा। इसमें टीआरक्यू वर्ष के दौरान आपूर्ति की जाने वाली वाहनों की संख्या का उल्लेख होगा।

डीजीएफटी ने कहा, 'इन आयातों के लिए वर्ष का अर्थ भारत में एक जनवरी से 31 दिसंबर तक की कैलेंडर अवधि होगा। डीजीएफटी जारी किए गए टीआरक्यू प्रमाणपत्रों की संचयी संख्या पर निगरानी रखेगा। निर्धारित टीआरक्यू सीमा पूरी होने के बाद कोई टीआरक्यू प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।'' ये प्रमाणपत्र अधिकतम 12 महीने या कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, वैध रहेंगे।

डीजीएफटी ने कहा, ''टीआरक्यू के तहत आयात करने वाले आयातक रियायती सीमा शुल्क का लाभ अंतिम खरीदार या उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।'' ब्रिटेन से भारत में आयात के लिए पारंपरिक इंजन वाले यात्री वाहनों का कोटा पांचवें वर्ष में विभिन्न श्रेणियों में बढ़कर 37,000 इकाई हो जाएगा। इसके साथ ही सीमा शुल्क क्रमिक रूप से घटकर अंतिम रूप से 10 फीसदी रह जाएगा। इसके बाद शुल्क में और कोई कटौती नहीं होगी।''

अधिसूचना के मुताबिक पहले वर्ष में 3,000 सीसी से अधिक (पेट्रोल) और 2,500 सीसी से अधिक (डीजल) इंजन क्षमता वाली कारों का कोटा 10,000 इकाई होगा। इन पर सीमा शुल्क 110 फीसदी से घटाकर 30 फीसदी किया जाएगा। 1,500 सीसी (पेट्रोल), 2,500 सीसी (डीजल) और 3,000 सीसी (पेट्रोल) इंजन क्षमता वाली कारों के लिए कोटा 5,000 इकाई होगा और इन पर शुल्क 66 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी किया जाएगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय के जारी दस्तावेज के अनुसार, 1,500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले जन बाजार (मास मार्केट) श्रेणी की कारों के लिए समझौते के पहले वर्ष में 5 हजार इकाइयों के आयात की अनुमति होगी और इन पर सीमा शुल्क 66 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी किया जाएगा।

पहले वर्ष में तीनों श्रेणियों में कुल 20 हजार यात्री कारों का आयात

समझौते के पहले वर्ष में इन तीनों श्रेणियों में कुल 20 हजार यात्री कारों के आयात की अनुमति होगी। भारत ने 40,000 ब्रिटिश पाउंड (सीआईएफ) से कम कीमत वाले वाहनों के लिए अपना बाजार नहीं खोला है। इससे बड़े पैमाने के बाजार वाले इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खंड को पूर्ण संरक्षण मिलेगा, जिसमें भारत टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी घरेलू कंपनियों के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व हासिल करना चाहता है।

भारत ने इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन चालित यात्री कारों के लिए पहले पांच वर्षों में कोई रियायत नहीं दी है। हालांकि, छठे वर्ष से 40,000 ब्रिटिश पाउंड (सीआईएफ) से 80,000 ब्रिटिश पाउंड (सीआईएफ) (दोनों सहित) कीमत वाले ऐसे वाहनों पर सीमा शुल्क 50 फीसदी कर दिया जाएगा और इनके लिए 400 इकाइयों का कोटा होगा। वहीं, 80,000 ब्रिटिश पाउंड (सीआईएफ) से अधिक कीमत वाले ऐसे वाहनों पर शुल्क 40 फीसदी होगा और इनके आयात की सीमा 4,000 इकाई निर्धारित की गई है।

रुकना चाहिए जनसंख्या विस्फोट

(विश्व जनसंख्या दिवस/ 11 जुलाई विशेष)

योगेश कुमार गोयल

जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो तेजी से बढ़ती आबादी के कारण ही हम सभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पहुंचाने में पिछड़ रहे हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल हो चुकी है। हालांकि विगत दशकों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार जुटाने के कार्यक्रम चलाए गए लेकिन बढ़ती आबादी के कारण ये सभी कार्यक्रम ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुए। देश में आबादी और संसाधनों के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है। वास्तविकता यही है कि विगत दशकों में देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ी, उस गति से कोई भी सरकार जनता के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की व्यवस्था करने में सफल हो ही नहीं सकती थी।

आज देश की बहुत बड़ी आबादी निम्न स्तर का जीवन जीने को विवश है। देश में करीब 40 प्रतिशत आबादी आजादी के बाद से ही गरीबी के आलम में जी रही है। गरीबी में जीवन गुजार रहे ऐसे बहुत से लोगों की यही सोच रही है कि उनके यहां जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतने ही ज्यादा कमाने वाले हाथ होंगे किन्तु यह सोच वास्तविकता के धरातल से परे है। लगातार बढ़ती महंगाई के जमाने में परिवार बड़ा होने से कमाने वाले हाथ ज्यादा होने पर जितनी आय बढ़ती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरतें और विभिन्न उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिनकी पूर्ति कर पाना सामर्थ्य से परे हो जाता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए सर्वाधिक जरूरी यही है कि घोर निर्धनता में जी रहे ऐसे लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के महत्व के बारे में जागरूक करने की ओर खास ध्यान दिया जाए क्योंकि जब तक इस कार्यक्रम में इन लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

देश में जनसंख्या वृद्धि का मुकाबला करने के लिए पिछले काफी समय से कुछ कड़े कानून बनाने की मांग हो रही है लेकिन इस दिशा में कुछ राज्य सरकारें दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को सरकारी नौकरी तथा स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारी से अयोग्य अघोषित करने जैसे जिस तरह के उपायों पर विचार कर रही हैं, उन्हें तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। हालांकि जनसंख्या वृद्धि मौजूदा समय में गंभीर चुनौती है लेकिन ऐसे उपायों को संवैधानिक नजरिये से भी तर्कसम्मत नहीं माना जाता। चीन में 1980 से पहले केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी, जिसका उल्लंघन करने पर दम्पति को न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाता था बल्कि सजा भी दी जाती थी लेकिन वहां यह नीति सफल नहीं हुई। इसीलिए चीन सरकार ने 2016 में इस नीति में बदलाव कर दो बच्चों की अनुमति दी और बाद में तीन बच्चों की अनुमति देनी पड़ी। चीन की तानाशाही सरकार द्वारा नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए दम्पत्तियों को तीन बच्चे करने की अनुमति क्यों दी गई, इसके कारण समझना भी जरूरी है। दरअसल वहां लोगों की सामान्य प्रजनन दर में निरन्तर गिरावट आ रही है और कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक यही स्थिति भारत में भी होनी है।

जनसंख्या में स्थायित्व और कामकाजी युवाओं की स्थिर संख्या के लिए महिलाओं की सामान्य प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए और चीन में यह दर निरन्तर गिर रही है। 1970 में चीन में यह दर 5.8 थी, जो 2015 में घटकर 1.6 और 2020 में केवल 1.3 ही रह गई जबकि बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ती गई। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स (एनबीएस) के अनुसार आने वाले समय में आबादी में अधिक उम्र वालों की संख्या बढ़ने से संतुलित विकास और जनसंख्या को लेकर दबाव बढ़ेगा। 1982 में हुई जनगणना में चीन की जनसंख्या में 2.1 फीसदी की सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी लेकिन उसके बाद जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जिसके लिए वहां की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा अपनाई गई दशकों पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी को जिम्मेदार माना जाता है।

विगत एक दशक में चीन की जनसंख्या करीब सात करोड़ बढ़ी लेकिन बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से चीन के लिए अलग ही समस्या उत्पन्न होने लगी है। दरअसल चीन को आशंका है कि अगले दस वर्षों में उसकी जनसंख्या में गिरावट आएगी, जिससे कामगारों की संख्या में कमी आने से उसकी खपत भी घटेगी। एनबीएस के आंकड़ों के मुताबिक चीन को जिन जनसांख्यिकीय संकट का सामना करना पड़ा था, वह और गहरा होने की उम्मीद थी, इसीलिए चीन को अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव करने पर विवश होना पड़ा।

जहां तक भारत की बात है तो यहां 1994 में महिलाओं की सामान्य प्रजनन दर 3.4 थी, जो घटकर 2015 में 2.2 रह गई थी यानी सामान्य के करीब। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जनसंख्या 2050 तक बढ़ने के बाद से गिरनी शुरू हो जाएगी और 2100 तक पहुंचते-पहुंचते सामान्य प्रजनन दर केवल 1.3 ही रह जाएगी। इसका अर्थ है कि तब अधिकांश परिवारों में केवल एक ही बच्चा होगा और भारत उसी स्थिति में खड़ा होगा, जिसमें वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद चीन खड़ा हुआ और उसे विगत सात वर्षों में दो बार अपनी जनसंख्या नीति में बड़ा परिवर्तन करना पड़ा। इसलिए टू चाइल्ड पॉलिसी जैसे कानूनों के जरिये जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों को व्यावहारिक नहीं माना जा रहा बल्कि इसके लिए डराने-धमकाने वाले कानूनों के बजाय लोगों में जागरुकता पैदा किया जाना सबसे जरूरी है।

बगैर कड़े कानूनों के देश के ऐसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, जहां साक्षरता दर ज्यादा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीब महिलाओं की प्रजनन दर करीब 3.2 है जबकि सम्पन्न महिलाओं में यह दर केवल 1.5 पाई गई है। इसी प्रकार अनपढ़ महिलाओं के औसतन 3.1 बच्चे होते हैं जबकि शिक्षित महिलाओं में यह संख्या औसतन 1.7 है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जनसंख्या विस्फोट का सीधा संबंध सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों से जुड़ा है। शिक्षा के अभाव में ही देश की बड़ी आबादी को छोटे परिवार के लाभ को लेकर जागरूक नहीं किया जा सका है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

IND – ENG सीरीज के बाद BCCI करेगा गंभीर-अय्यर के साथ मीटिंग, टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन की होगी पड़ताल

नई दिल्ली एजेंसी। पहले आयरलैंड और अब इंग्लैंड. च टूर पर टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद BCCI हरकत में आ गया है. भारतीय क्रिकेट एंड कंट्रोल बोर्ड ने सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मीटिंग करने का फैसला लिया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बारे में बृष्टड्ढ के सचिव देवजीत सैकिया ने जानकारी दी है. उन्होंने टीम के मौजूदा प्रदर्शन पर चिंता जाहिर करते हुए कोच और कप्तान के साथ उसकी समीक्षा करने की बात कही है.

टीम इंडिया के प्रदर्शन की होगी पड़ताल- देवजीत सैकिया

बृष्टड्ढ के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने अपने बयान में कहा कि वो टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखकर चिंतित है.

सीरीज के खत्म होने के बाद वो कप्तान और कोच के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, ताकि ये समझा जा सके कि कमी कहां रह गई उन्होंने कहा कि वो उन समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे ताकि भारतीय टीम फिर से अपनी पुरानी इमेज और लय को हासिल कर सके.

आयरलैंड में पहली बार क्लीन स्वीप

टीम इंडिया के च टूर की शुरुआत आयरलैंड दौरे से हुई थी, जहां भारत को 2 अ20 की सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. ये बतौर अ20 कप्तान श्रेयस अय्यर की पहली सीरीज थी. वहीं ये पहली बार था जब आयरलैंड ने भारत के खिलाफ कोई अ20 मैच और सीरीज दोनों जीती थी.

इंग्लैंड में भी गंवाई सीरीज, अब बादशाहत पर लटकी तलवार

आयरलैंड के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड तो पहुंची लेकिन हालात यहां भी नहीं बदले. भारतीय टीम 5 अ20 के पहले 4 मैचों में ही सीरीज गंवा चुकी है. एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा जबकि 3 मैच जीतकर इंग्लैंड सीरीज में 0-3 की अजेय बढ़त ले चुका है. अब टीम इंडिया पर क्लीन स्वीप और अ20 रैंकिंग में बादशाहत के छिने जाने का भी खतरा बढ़ गया है. भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी अ20 11 जुलाई को साउथैम्प्टन में खेलना है.

टीम इंडिया का यही रहा हाल, तो ओलंपिक से हो जाएगी बाहर? क्या है क्वालिफिकेशन का नियम

नई दिल्ली एजेंसी।
टीम इंडिया पिछले लंबे समय से टी20 क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए हुए है. साल 2022 से ही आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में भारत नंबर-1 की पोजीशन पर काबिज है. लेकिन हाल ही में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया का जो हश्र हुआ है, उसने भारतीय क्रिकेट फैंस की चिंताएं बढ़ा दी हैं. पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद अब न सिर्फ भारत का नंबर-1 का ताज छिनने की कगार पर है, बल्कि इसका सीधा असर लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के क्वालिफिकेशन पर भी पड़ सकता है.

लगातार हार से रेटिंग पॉइंट्स में भारी गिरावट

भारतीय टीम ने जब इस यूके दौरे का आगाज किया था, तब उसके खाते में कुल 275 रेटिंग पॉइंट्स थे. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को 2-0 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, जिससे रेटिंग पॉइंट्स घटकर 272 हो गए. अब इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में भारत अब तक खेले गए चार मुकाबलों में से तीन मैच गंवा चुका है, वहीं एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के रेटिंग पॉइंट्स गिरकर 269 पर आ गए हैं.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम लगातार जीत का लुत्फ उठा रही है और वह 267 रेटिंग पॉइंट्स के साथ भारत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है. अब दोनों टीमों के बीच सिर्फ 2 पॉइंट्स का फासला रह गया है. ऐसे में अगर भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला भी हार जाती है, तो वह नंबर-1 की कुर्सी से हाथ धो बैठेगी.

भारतीय टीम का यूके दौरा अभी तक काफी खराब रहा है. 6 मैचों के बाद भी उसे एक जीत हासिल नहीं हुआ है. टीम का ये प्रदर्शन ओलंपिक 2028 के क्वालिफिकेशन पर असर डाल सकता है.

ओलंपिक क्वालिफिकेशन का क्या है नियम?

क्रिकेट फैंस के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस रैंकिंग का ओलंपिक से क्या लेना-देना है. दरअसल, साल 2028 में होने वाले लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है. इसके क्वालिफिकेशन का जो नियम है, उसके मुताबिक भारतीय पुरुष टीम को अगर ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करना है, तो उसे साल 2026 के अंत तक आईसीसी टी20 रैंकिंग में एशियाई टीमों के बीच टॉप पर बने रहना होगा.

अगर, टीम इंडिया का ग्राफ इसी तरह गिरता रहा, तो आने वाले समय में उसे तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. राहत की बात बस इतनी है कि एशियाई टीमों की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान की टीम फिलहाल 240 रेटिंग पॉइंट्स के साथ कुल रैंकिंग में छठे स्थान पर है, जो भारत से काफी पीछे है. लेकिन अगर भारत लगातार मैच हारता रहा, तो यह अंतर भी कम हो सकता है.

इंग्लैंड सीरीज के बाद भारत का शेड्यूल

इंग्लैंड का यह दौरा खत्म होने के बाद भारतीय टीम के पास अपनी रैंकिंग को सुधारने और ओलंपिक का टिकट सुरक्षित करने के लिए कई सीरीज खेलनी हैं.

जुलाई के अंत में जिम्बाब्वे दौरा- तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज.

अक्टूबर की शुरुआत में वेस्टइंडीज से टक्कर- घरेलू मैदान पर 5 मैचों की टी20 सीरीज.

अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड दौरा- कीवी टीम के खिलाफ उनके घर में 5 मैचों की टी20 सीरीज.

साल के अंत में श्रीलंका से सामना- अपने घर पर तीन मैचों की टी20 सीरीज.

मोहम्मद नबी के बेटे का तूफान, सिर्फ 28 गेंदों पर जड़ा शतक, 20 ओवर में टीम पहुंची 300 पार

दिल्ली एजेंसी।
अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी के 19 साल के बेटे हसन ईसाखिल ने एक तूफानी पारी खेलकर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. अफगानिस्तान 11 और उजबेकिस्तान की टीमों के बीच इकलौते अनऑफिशियल टी20 मुकाबले में हसन ईसाखिल ने विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए एक यादगार शतक जड़ा. उनकी इस तूफानी पारी के चलते अफगानिस्तान 11 की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब रही.

मोहम्मद नबी के बेटे का तूफानी शतक

इस मैच में बतौर ओपनर क्रीज पर उतरे हसन ईसाखिल ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे. उन्होंने उजबेकिस्तान के गेंदबाजों को संभलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया और मैदान के हर कोने में गगनचुंबी छक्के और करारे चौके बरसाए. हसन ने सिर्फ 28 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, जो टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज पारियों में से एक है. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टी20 क्रिकेट को पूरी तरह वीडियो गेम में तब्दील कर दिया.

हसन ईसाखिल ने इस पारी में कुल 34 गेंदों का सामना किया और 352.94 की स्ट्राइक रेट से 120 रन ठोके. उनकी इस पारी में 4 चौके और 16 छक्के शामिल रहे. लेकिन फिर कुछ दिक्कत का सामना करते के चलते उन्हें रिटायर्ड आउट होना पड़ा. उन्होंने कप्तान इमरान मीर के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 181 रनों की साझेदारी भी की. इस तूफानी शुरुआत के चलते अफगानिस्तान 11 की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 323 रन बनाने में कामयाब रही. जिसमें इमरान मीर के 74 रन भी शामिल रहे.

इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार

हसन ईसाखिल पिछले कुछ समय से अपने दमदार प्रदर्शन के चलते अफगानिस्तान क्रिकेट में छाए हुए हैं. वो कुछ लीग में अपने पिता मोहम्मद नबी के साथ भी खेलते हुए नजर आ चुके हैं. अफगानिस्तान के घरेलू टूर्नामेंट में भी दोनों साथ खेलते हैं.

बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम घोषित

शुम्बा और न्यूमैन न्यामहुरी को मौका

हरारे। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली 3 टी20 मैचों की घरेलू सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट ने बुधवार को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। टीम की कमान सिकंदर रजा के हाथ में है। इस टीम में ज्यादातर वही खिलाड़ी हैं जो टी20 विश्व कप 2026 में जिम्बाब्वे को सुपर-8 तक पहुंचाने वाले कैंपेन का हिस्सा रहे थे। हरारे में चल रही वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद 15, 17 और 19 जुलाई को बुलावायो में 3 टी20 मैच खेले जाने हैं। टीम में दो

बदलाव हुए हैं। युवा तेज गेंदबाज न्यूमैन न्यामहुरी और बल्लेबाज मिल्टन शुम्बा को शामिल किया गया है। न्यामहुरी ने टी20 फॉर्मेट में अभी तक डेब्यू नहीं किया है। शुम्बा ऑस्ट्रेलिया में 2022 टी20 विश्व कप के बाद पहली बार टी20 टीम में लौटे हैं। बल्लेबाज बेन कुरेन, जिन्हें इस साल की शुरुआत में ब्रेंडन टेलर की चोट के बाद टी20 विश्व कप टीम में शामिल किया गया था, ने अपनी जगह बरकरार रखी है। ग्रेम क्रेमर बाएं हाथ में इंजरी की वजह से चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

चयनकर्ता संयोजक डेविड मुटेंडेरा ने कहा कि टीम का चयन करते समय निरंतरता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। उन्होंने कहा, 'टी20 विश्व कप ने दिखाया कि यह ग्रुप क्या करने में काबिल है, इसलिए निरंतरता हमारे लिए एक जरूरी बात थी। हम सुपर आठ तक पहुंचने वाली टीम के कोर को एक साथ रखना चाहते थे, साथ ही उन खिलाड़ियों के लिए भी जगह बनाना चाहते थे जिन्होंने अपने प्रदर्शन से अपने लिए मौके बनाए हैं। यह सीरीज टीम को आगे बढ़ने का एक और मौका देती है क्योंकि हम आगे के बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं।'

जिम्बाब्वे टीम

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजराबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा।

लॉर्ड्स में महिलाओं का टेस्ट मैच एक शानदार मौका

इसका बेसब्री से इंतजार है: भारतीय कोच मजूमदार

लंदन। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 10 जुलाई से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इकलौता टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस खास मौके पर खुशी जाहिर करते हुए भारतीय हेड कोच अमोल मजूमदार ने बुधवार को कहा कि 'होम ऑफ क्रिकेट' में टेस्ट मैच खेलना किसी भी भारतीय क्रिकेटर का सबसे बड़ा सपना होता है। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजूमदार ने कहा, 'यह सोचकर ही हैरानी होती है कि लॉर्ड्स में यह पहला टेस्ट मैच (विमेंस) है। इसके बावजूद, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। मैं इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह एक शानदार मौका है और हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसी भी भारतीय क्रिकेटर के लिए टेस्ट मैच खेलना ही एक सपना होता है, फिर लॉर्ड्स में खेलने की बात ही अलग है। मुझे यकीन है कि इस मुकाबले में जो भी खिलाड़ी सफेद जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे, उन्हें लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेलने पर गर्व होगा।' उन्होंने कहा, 'हमने ड्रेसिंग रूम में हमेशा यही बात कही है। पारंपरिक रूप से हमने टेस्ट मुकाबलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही हर कोई लॉर्ड्स में होने वाले टेस्ट मैच के बारे में बात कर रहा था। अब वह समय आ गया है, इसलिए खिलाड़ी निश्चित रूप से इसे लेकर उत्साहित होंगे।'

भारत ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन किया। लीग स्टेज से बाहर होने के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के विरुद्ध इस टेस्ट मैच में उतरेगी। मजूमदार ने स्वीकार किया है कि हालांकि प्रदर्शन 'मिला-जुला' रहा, लेकिन टीम ने सफलतापूर्वक अपना ध्यान सबसे लंबे फॉर्मेट पर लगा लिया है।

उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो, यह मिला-जुला रहा है। हमें हार से उबरना था। हम निश्चित रूप से निराश थे। हमारा वर्ल्ड कप बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद, टीम का जज्बा सामने आना जरूरी था और हमें उस दौर से बाहर निकलकर जल्द ही टेस्ट मैच की तैयारी में जुटना था। मुझे लगता है कि हम ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। हमने वर्म्सले क्रिकेट क्लब में तैयारी के पांच बहुत अच्छे दिन बिताए। यह एक खूबसूरत मैदान है और तैयारी के लिए एकदम सही जगह है और फिर यहां लॉर्ड्स में भी। हमारी तैयारी अच्छी रही है।'

टैमी ब्यूमोंट भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लेंगी संन्यास

लंदन। इंग्लैंड की अनुभवी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। टैमी भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले मुकाबले के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगी। टैमी अपने 17 साल के शानदार करियर का अंत इस मशहूर मैदान पर टेस्ट मैच के साथ करेंगी, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई से होगी। नवंबर 2009 में अपने अंतरराष्ट्रीय सफर की शुरुआत करने वाली टैमी ने इंग्लैंड के लिए सभी फॉर्मेट में कुल 260 मैच खेले, जिसमें 7,325 रन बनाए। टैमी वनडे फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक 12 शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी हैं, जो साल 2017 में घरेलू मैदान पर इंग्लैंड की ऐतिहासिक महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत की मुख्य सूत्रधार थीं। उस टूर्नामेंट में टैमी ने सर्वाधिक 410 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की तरफ से जारी एक बयान में टैमी ने कहा, 'करीब 17 साल तक इंग्लैंड के लिए खेलना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा है। जब छोटी उम्र में क्रिकेट खेलने का शौक जगा, तब मुझे शायद ही पता था कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलना भी एक विकल्प हो सकता है। यह सोचकर मुझे बहुत खुशी होती है कि कितनी लड़कियां और लड़के इससे प्रेरित हुए हैं। हम हमेशा अगली पीढ़ी के लिए इस विरासत को आगे बढ़ाना चाहते थे, और अब मेरे लिए यह मौका आ गया है कि मैं इंग्लैंड के खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी को यह जिम्मेदारी सौंप दूं। लॉर्ड्स में होने वाला यह टेस्ट मैच, जो लॉर्ड्स में महिलाओं का पहला टेस्ट है, मेरे करियर को अलविदा कहने का सबसे सही मौका है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा करियर इतना शानदार होगा।'

35 वर्षीय टैमी इंग्लैंड की उन दो महिला खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने खेल के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है। टैमी टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली इंग्लिश महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने साल 2023 में विमेंस एशेज के दौरान ट्रेंट ब्रिज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 208 रन बनाए थे। टैमी ब्यूमोंट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह घरेलू क्रिकेट में 'द ब्लेज' और 'द हंड्रेड' में 'बर्मिंघम फीनिक्स' के लिए खेलना जारी रखेंगी। उन्होंने कहा, 'मैं घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखूंगी, लेकिन अपने शानदार सपोर्ट के लिए सभी फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं।

फीफा विश्व कपः मोरक्को को झटका

फॉरवर्ड सैबारी फ्रांस के खिलाफ क्वार्टर-फाइनल से हुए बाहर

नई दिल्ली। फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल में फ्रांस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले मोरक्को को बड़ा झटका लगा है। उनके मुख्य फॉरवर्ड इस्माइल सैबारी चोट के कारण इस अहम मैच से बाहर हो गए हैं। मोरक्को के हेड कोच मोहम्मद ओआबी ने गुरुवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैबारी के बाहर होने की पुष्टि की। ओआबी के अनुसार, कनाडा के खिलाफ राउंड ऑफ 16 की जीत के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट लगने के बाद यह फॉरवर्ड समय पर ठीक नहीं हो सका। हालांकि, कोच को उम्मीद है कि अगर उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, तो 25 वर्षीय खिलाड़ी फिट हो जाएगा। मैच से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ओआबी ने कहा, 'वह तैयार नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह उनके लिए टूर्नामेंट का अंत नहीं है।'

सैबारी मौजूदा टूर्नामेंट में अफ्रीकी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने ग्रुप स्टेज के तीनों मैचों में गोल किए और राउंड ऑफ 32 में नीदरलैंड के खिलाफ निर्णायक

शूटआउट में पेनल्टी को गोल में बदला। उनकी अनुपस्थिति के कारण मोरक्को को 2022 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम के खिलाफ अधिक रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ सकती है।

फीफा ने फ्रांस और मोरक्को के बीच क्वार्टर-फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह से अर्जेंटीना के अधिकारियों की टीम नियुक्त करके एक बड़ी बहस छेड़ दी है। 2026 टूर्नामेंट में यह पहली बार है जब किसी मैच का संचालन पूरी तरह से एक ही देश के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। हालांकि, मोरक्को के कोच ने अधिकारियों के प्रभाव को कम करके आंका है।

मैच से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेफरी के बारे में उन्होंने कहा, 'हम एक बहुत अनुभवी रेफरी की बात कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं। हम इस तरह के मैचों के लिए अनुभवी रेफरी चाहते हैं। इसलिए हम बहुत शांत हैं। नीदरलैंड्स का सामना करने से पहले हमारे मैच में एक डच रेफरी था और उसने बहुत अच्छा काम किया था।

अमेरिकी पॉलिसी बदलेंगे भारतीय दिमाग! फेड ने इस त्रिमूर्ति को किया खास टास्क फोर्स में शामिल

दिल्ली एजेंसी।
US फेडरल रिजर्व ने गुरुवार को पांच टास्क फोर्स के लीडर्स के नामों का ऐलान किया. ये टास्क फोर्स इस बात की समीक्षा करेंगी कि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी (मौद्रिक नीति) कैसे लागू करता है. चुने गए लोगों में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री रघुराम राजन और राज चेट्टी, और माइक्रोसॉफ्ट की एग्जीक्यूटिव आशा शर्मा शामिल हैं, जो तीन पैनल की अगुवाई करेंगे. फेड के चेयरमैन केविन वॉर्श ने पद संभालने के बाद 17 जून को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पहल का ऐलान किया था. वॉर्श ने एक बयान में कहा कि कीमतों में स्थिरता और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के लिए फेडरल रिजर्व का कमिटमेंट अटूट है. साथ ही, हम अपने मैंडेट (दायित्व) को पूरी गंभीरता से निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने आगे कहा कि मुझे गर्व है कि अलग-अलग क्षेत्रों के बेहतरीन एक्सपर्ट्स एक संस्था के तौर पर हमारे कामकाज को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ काम करने को तैयार हुए हैं. मकसद साफ़ है- यह पक्का करना कि फेड इस अहम समय में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हो.
फेड ने कहा कि हर टास्क फोर्स की अगुवाई एकेडेमिया, बिजनेस और सेंट्रल बैंकिंग के एक्सपर्ट्स मिलकर करेंगे, जिन्हें फेडरल रिजर्व के स्टाफ का सहयोग मिलेगा. ये पैनल आज़ादी से काम करेंगे और फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (एफओएमसी) को सबूतों पर आधारित सुझाव देंगे. वॉर्श को उम्मीद है कि यह समीक्षा साल के आखिर तक पूरी हो जाएगी.
रघुराम राजन क्या करेंगे?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, हार्वर्ड के अर्थशास्त्री कैरेन डायनन और फेडरल रिजर्व के पूर्व गवर्नर जेरेमी स्टीन के साथ मिलकर 'बैलेंस शीट पॉलिसी' टास्क फोर्स में काम करेंगे.
यह पैनल फेडरल रिजर्व की मौजूदा बैलेंस शीट व्यवस्था की कॉस्ट, फ़ायदों और संस्थागत असर की जांच करेगा, जिसमें एसेट होल्डिंग्स और मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने में उनकी भूमिका शामिल है. वॉर्श पहले भी कह चुके हैं कि फेड की बैलेंस शीट, जिसकी कीमत अभी लगभग 6.7 ट्रिलियन डॉलर है, को कम किया जाना चाहिए.
राजन अभी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं. 2013 से 2016 के बीच आरबीआई गवर्नर के तौर पर, उन्होंने भारत को फ्रैजाइल फाइव (बाज़ार में उथल-पुथल) से निपटने में मदद की, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया और देश के महंगाई-लक्ष्यीकरण (inflation-targeting) फ्रेमवर्क को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई.
राज चेट्टी क्या करेंगे?
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री राज चेट्टी, वॉलमार्ट के पूर्व सीईओ डग मैकमिलन और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अर्थशास्त्री केविन मर्फी के साथ मिलकर 'डाटा' टास्क फोर्स की अगुवाई करेंगे. यह ग्रुप असल दुनिया के उन आर्थिक संकेतों की क्वालिटी और समय पर उपलब्धता को बेहतर बनाने पर ध्यान देगा, जो फेडरल रिजर्व के पॉलिसी फैसलों में मदद करते हैं. चेटी को अमेरिका में आर्थिक गतिशीलता, असमानता और लेबर मार्केट का अध्ययन करने के लिए बड़े प्रशासनिक और रियल-टाइम डाटासेट का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है.
आशा शर्मा क्या करेंगी?
माइक्रोसॉफ्ट की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आशा शर्मा, वेंचर कैपिटलिस्ट मार्क आंद्रेसेन और स्टैनफोर्ड के अर्थशास्त्री चार्ल्स आई. जोन्स के साथ मिलकर प्रोडक्टिविटी और जॉब्स टास्क फोर्स में काम करेंगी. यह पैनल प्रोडक्टिविटी, रोज़गार और आर्थिक विकास पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती हुई जनरल-पर्पस टेक्नोलॉजी के आर्थिक असर का आकलन करेगा. उम्मीद है कि इसके नतीजों से फेडरल रिजर्व को यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी कि, एआई और दूसरी टेक्नोलॉजी में तरक्की कैसे लेबर मार्केट पर असर डाल सकती है और भविष्य के मॉनेटरी पॉलिसी फैसलों को आकार दे सकती है.
दूसरी टास्क फोर्स
बाकी दो टास्क फोर्स फेडरल रिजर्व के पॉलिसी फ्रेमवर्क के अहम पहलुओं पर ध्यान देंगी. कम्युनिकेशंस टास्क फोर्स, जिसकी अगुवाई पीटर फिशर, अर्मीनियो फ्रागा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मर्विन किंग करेंगे, यह समीक्षा करेगी कि अनिश्चितता के समय में फेड अपनी पॉलिसी पर चर्चा और फैसलों के बारे में कैसे जानकारी देता है.
इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क टास्क फोर्स, जिसकी अगुवाई हार्वर्ड के अर्थशास्त्री ग्रेग मैनकिव, नोबेल पुरस्कार विजेता थॉमस सार्जेंट और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पूर्व सलाहकार विलियम व्हाइट करेंगे, यह फिर से देखेगी कि सेंट्रल बैंक महंगाई के कारणों को कैसे समझता है और उन पर कैसे रिस्पांस देता है.

34 करोड़ PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी! EPFO भेजने जा रहा है 1.44 लाख करोड़ रुपये का ब्याज

दिल्ली एजेंसी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सदस्यों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. EPFO 15 जुलाई तक करीब 34 करोड़ सदस्यों के खातों में वित वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए 8.25 फीसदी की दर से ब्याज जमा करेगा. इसके तहत कुल 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सदस्यों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इस बार ब्याज जमा करने की प्रक्रिया नए CITES 2.01 सिस्टम के जरिए ऑटो-प्रोसेस होगी, जिससे काम पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और पारदर्शी होगा.
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि ब्याज ट्रांसफर करने से पहले ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस रिकॉर्ड का सत्यापन कर रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद राशि सीधे सदस्यों के खातों में भेज दी जाएगी.

नया पोर्टल देगा कई सुविधाएं
मंडाविया के मुताबिक, EPFO का नया CITES 2.01 सदस्य पोर्टल सदस्यों के लिए कई सुविधाएं लेकर आएगा. इस पोर्टल पर एक ही जगह PF बैलेंस, क्लेम की स्थिति, पेंशन रिकॉर्ड और अन्य जरूरी सेवाओं की जानकारी मिल सकेगी. इससे अलग-अलग पोर्टल या प्रक्रिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.अब सदस्यों को अपने खाते की जानकारी देखने और क्लेम से जुड़ी जानकारी हासिल करने में पहले की तुलना में कम समय लगेगा.
अब ब्याज के लिए महीनों इंतजार नहीं
अब तक EPFO सदस्यों को हर साल ब्याज की राशि खाते में दिखाई देने के लिए अक्टूबर या नवंबर तक इंतजार करना पड़ता था. लेकिन नए सिस्टम के लागू होने के बाद ब्याज की पूरी प्रक्रिया काफी तेज हो गई है. इससे लाखों कर्मचारियों को समय पर अपने पीएफ खाते का अपडेट मिल सकेगा.
एडवांस क्लेम के नियम में भी हुए आसान
ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट सीमा भी बढ़ा दी है. पहले पात्र और दस्तावेज पूरा कर चुके सदस्य 1 लाख रुपये तक का एडवांस क्लेम ऑटो-सेटलमेंट के जरिए कर सकते थे, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है.नई व्यवस्था में क्लेम जमा करने से पहले ही सिस्टम दस्तावेजों और जानकारी की ऑटोमैटिक जांच करेगा. यदि किसी तरह की कमी होगी तो उसकी जानकारी पहले ही मिल जाएगी. साथ ही सदस्य यह भी देख सकेंगे कि वे अलग-अलग श्रेणियों में कितनी राशि निकालने के पात्र हैं. इससे क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना कम होगी और पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी.

फोर्ड ने कोयंबटूर में खोला तीसरा वैश्विक केंद्र, भारत में तकनीक और डेटा पर जोर

600 से अधिक कर्मचारियों के साथ यह कार्यालय वैश्विक परिचालन मजबूत करेगा

नई दिल्ली ।
अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी की सहायक इकाई फोर्ड बिजनेस सॉल्यूशंस (एफबीएस) ने भारत में अपने तीसरे वैश्विक क्षमता केंद्र का कोयंबटूर में उद्घाटन किया है। यह नया केंद्र फोर्ड के वैश्विक परिचालन को मजबूत करेगा और चेन्नई स्थित एफबीएस केंद्र के लिए एक समर्पित बिजनेस कंटिन्यूटी केंद्र (बीसीसी) के तौर पर काम करेगा, जो वैश्विक लेखांकन, क्रेडिट और कारोबारी परिचालन टीमों को सेवाएं देगा। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, भविष्य में भारत में फोर्ड की लगभग 50 फीसदी वृद्धि तकनीक, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्रों से आएगी। कोयंबटूर केंद्र में शुरुआती चरण में 600 से अधिक कर्मचारियों समेत करीब 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यह एसवीबी टेक पार्क में 82,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में तीन मंजिलों में फैला है। एफबीएस इंडिया की प्रमुख और प्रबंध निदेशक गंगाप्रिया चक्रवर्ती ने कहा, यह केंद्र हमारी बिजनेस कंटिन्यूटी रणनीति का अहम हिस्सा है, जो मौसम या अन्य कारणों से चेन्नई के कामकाज प्रभावित होने पर भी वैश्विक बाजारों को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करेगा। अगस्त 2022 में फोर्ड द्वारा भारत में अपने विनिर्माण संयंत्र बंद करने के बावजूद, एफबीएस इंडिया में फिलहाल 12,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। चेन्नई का ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर फोर्ड के वैश्विक सफल मॉडलों के डिजाइन व विकास में महत्वपूर्ण रहा है, जबकि बेंगलुरु में भी एक तकनीकी इनक्यूबेशन सेंटर है। कोयंबटूर कार्यालय को सहयोगात्मक और हाइब्रिड कार्य प्रणाली के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 230 से अधिक वर्कस्टेशन, मीटिंग रूम और फोकस रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं।

शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद

सेंसेक्स 238, निफ्टी 81 अंक ऊपर आया

मुम्बई ।
घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार में ये तेजी दुनियां भर से मिले-जुले संकेतों के बाद भी खरीददारी हावी रहने से आई है। आज ज्यादा प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर खुले और पूरे दिन मजबूत बने रहे। हालांकि, कारोबारी सत्र के अंतिम पलों में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली पर इसके बाद भी बाजार ने अपनी तेजी बरकरार रखी। दिन के अंत में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 238 अंक उछलकर 76,741 के स्तर पर बंद हुआबंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 81 अंकों की मजबूती के साथ ही 23,962 के स्तर पर बंद हुआ, जिससे निवेशकों में उत्साह का माहौल बना रहा। यह प्रदर्शन वैश्विक बाजारों से मिल रहे मिश्रित संकेतों के बावजूद भारतीय बाजार की आंतरिक मजबूती को दर्शाता है।
यह तेजी केवल मुख्य सूचकांकों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी जबरदस्त उछाल रहा। , जिसने बाजार की सकारात्मक भावना को और मजबूत किया। निवेशकों ने छोटे और मझोले आकार की कंपनियों में खासा उत्साह दिखाय। निफ्टी स्मॉलकैप 100 में प्रभावशाली 1.80 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 ने भी 1.38 फीसदी की शानदार रैली दिखाई। यह व्यापक बाजार में आत्मविश्वास बढ़ने और निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता में वृद्धि का संकेत है।
निफ्टी 50 के भीतर, कुछ कंपनियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और बाजार को ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सन फार्मा सबसे आगे रहा, जिसने 2.68 फीसदी की बढ़त हासिल की। इसके बाद, भारती एयरटेल में 2.28 फीसदी, बजाज

फिनसर्व में 2.17 फीसदी और इंटरग्लोब में 2.06 फीसदी की शानदार तेजी दर्ज की गई।
हालांकि, बाजार की इस समग्र तेजी के बीच, कुछ शेयरों को नुकसान भी उठाना पड़ा। निफ्टी 50 की कंपनियों में डॉ रेड्डीज सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जिसमें 5.90 फीसदी की बड़ी गिरावट देखी गई। इसके बाद, इंफोसिस में 1.74 फीसदी, मारुति सुजुकी में 1.60 फीसदी, एनटीपीसी में 1.44 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिसने बाजार के कुछ क्षेत्रों पर दबाव बनाया। इससे पहले आज सुबह के शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 भी 111.35 अंकों की बढ़त के साथ ही 23,993.40 के स्तर पर पहुंचा, जो जल्द ही 24,000 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के करीब पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स भी 342 अंक बढ़कर 76,845.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

सरकार ने किया काम, अब उद्योग की बारी, सीईए का एआई चुनौती पर जोर

एआई से निपटने को कौशल और नवाचार में निवेश जरूरी

नई दिल्ली ।
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को उद्योगों से कृत्रिम मेधा (एआई) से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण और नवाचार में निवेश करने का आग्रह किया। सीआईआई जीसीसी शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने बजट में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) को समर्थन देकर अपना काम कर दिया है, अब उद्योग की बारी है। नागेश्वरन ने बताया कि केंद्रीय बजट में जीसीसी के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग सेफ हार्बर व्यवस्था को सरल बनाकर और छोटे शहरों तक विस्तार को प्रोत्साहित कर सरकार ने उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग पूरी की है। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि एआई ने पुराने कारोबारी मॉडल को चुनौती दी है, जिससे नियमित और दोहराए जाने वाले कार्य प्रभावित होंगे। उन्होंने आगाह किया कि केवल कम लागत पर आधारित मॉडल जोखिम में हैं, और उद्योगों को लागत-आधारित मॉडल से क्षमता-आधारित तथा निष्पादन से नवाचार की ओर बढ़ना होगा। सीईए ने उद्योगों से क्षमता निर्माण और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार रनवे तैयार कर सकती है, लेकिन विमान नहीं उड़ा सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि सफलता से आत्मसंतोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धी देश अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, लागत बढ़ रही है और कुशल प्रतिभा की

उपलब्धता लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। भारत को दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त इसी पर निर्भर करेगी कि वह एआई के लिए स्वयं को कितना तैयार करता है।

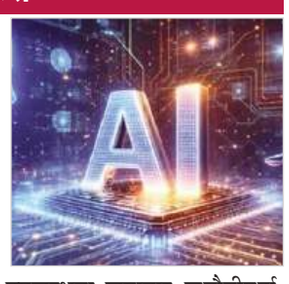

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मिलेगी गति, प्रमुख कलपुर्जों पर सीमा शुल्क समाप्त

केंद्र सरकार ने डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल जैसे सामानों पर बीसीडी हटाई

नई दिल्ली ।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन ने गुरुवार को सरकार के उस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उपयोग होने वाले प्रमुख कलपुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) को समाप्त कर दिया गया है। कृष्णन ने इस कदम को देश की मूल्य श्रृंखला को और मजबूत बनाने तथा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा उद्योग को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण बदलाव करार दिया। एक कार्यक्रम से इतर बातचीत में सचिव कृष्णन ने बताया कि यह निर्णय उद्योग जगत की ओर से लगातार किए गए अनुरोधों का परिणाम है। वित्त मंत्रालय के समक्ष मामला उठाने के बाद अब इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं। उनका मानना है कि यह पहल विशेष रूप से देश के इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा उद्योग के लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन होगी।
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य से यह छूट प्रदान की है। इसके तहत डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल जैसे प्रमुख कलपुर्जों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले सामान पर बुनियादी सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ेंगीं रसोई बजट पर दोहरी मार

महंगे आयात और घरेलू उत्पादन में संभावित गिरावट से फिलहाल राहत की उम्मीद कम

मुंबई ।
आयातित खाद्य तेलों की लगातार बढ़ती कीमतें और कमजोर मानसून के कारण घरेलू तिलहन उत्पादन पर मंडराते खतरे के चलते आने वाले महीनों में रसोई का बजट और बढ़ सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में महंगी खरीद और घरेलू उत्पादन में संभावित गिरावट के कारण उपभोक्ताओं को तत्काल राहत की संभावना नहीं है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार सरसों, सोयाबीन और पाम तेल की औसत खुदरा कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में 10-12 प्रतिशत अधिक हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक बढ़ती परिवहन लागत, कमजोर रुपया और प्रमुख उत्पादक देशों द्वारा खाद्य तेल का बायोडीजल में बढ़ता उपयोग आयात लागत को बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया का नया बी50 बायोडीजल कार्यक्रम वैश्विक बाजार में पाम तेल की उपलब्धता को और कम करेगा, जिससे कीमतें और बढ़ सकती हैं। वहीं इस वर्ष कमजोर और असमान

मानसून का असर घरेलू तिलहन उत्पादन, विशेषकर सोयाबीन और मूंगफली पर पड़ने की आशंका है। गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में बुआई का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में काफी पीछे चल रहा है। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का अनुमान है कि इन चुनौतियों के कारण भारत की खाद्य तेल आयात पर निर्भरता और बढ़ेगी, जो वर्ष 2025-26 तक 16.8 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।

देश के आठ शहरों में प्रीमियम घरों का दबदबा किफायती खंड पिछड़ा

जनवरी-जून 2026 में 8 शहरों में कुल बिक्री मामूली बढ़कर 1.71 लाख इकाई

नई दिल्ली ।
रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश के आठ प्रमुख शहरों में जनवरी-जून 2026 की अवधि में आवासीय बिक्री में 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जो 1.71 लाख इकाई तक पहुंच गई। इस अवधि में प्रीमियम मकानों की मांग में उल्लेखनीय उछाल देखा गया, जिनकी कुल बिक्री में 54 प्रतिशत की प्रभावशाली हिस्सेदारी रही। नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल बिक्री 1,71,471 इकाई रही, जो पिछले साल की 1,70,201 इकाई से मामूली अधिक है। इस वृद्धि में एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले मकानों की मुख्य भूमिका रही। वहीं, किफायती (50 लाख रुपये से कम) मकानों की बिक्री 15 प्रतिशत घटकर 32,063 इकाई (कुल बिक्री का 19 फीसदी) रह गई, जबकि मध्यम आय वर्ग (50 लाख से 1 करोड़ रुपये) के मकानों की बिक्री पांच प्रतिशत घटकर 46,490 इकाई (कुल बिक्री का 27 फीसदी) रही। आठ शहरों में से दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर सभी जगह आवास बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई, जहां सालाना आधार पर सात प्रतिशत की गिरावट आई।
इस वर्ष की पहली छमाही में नए आवासों की पेशकश चार प्रतिशत बढ़कर 1,87,350 इकाई हो गई। नाइट फ्रैंक इंडिया ने कहा कि बाजार के बुनियादी कारक मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू आय में वृद्धि, खरीदारों की बदलती आकांक्षाएं और गृह स्वामित्व में बढ़ता विश्वास प्रीमियम खंड को बल दे रहा है। शहरीकरण, बुनियादी ढांचा निवेश व स्थिर आर्थिक माहौल आवासीय बाजार को निरंतर सहारा दे रहे हैं।

तेल बाजार में विरोधाभास यूएस में कच्चे तेल का भंडार बढ़ा पर पेट्रोल-डीजल का घटा

पश्चिम एशिया में तनाव से कच्चे तेल में उछाल, डॉलर भी मजबूत

नई दिल्ली ।
अमेरिका के ऊर्जा बाजार से मिले नए आंकड़े मिले-जुले संकेत दे रहे हैं। जहां एक ओर कच्चे तेल का भंडार बढ़ा है, वहीं पेट्रोल और डीजल के स्टॉक में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच पश्चिम एशिया में गहराते भू-राजनीतिक तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर दोनों को मजबूती दी है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) के अनुसार 3 जुलाई को समाप्त सप्ताह में कच्चे तेल का भंडार 29.98 लाख बैरल बढ़कर 41.13 करोड़ बैरल हो गया, जो 10 हफ्तों की गिरावट के बाद पहली बार बढ़ा है। हालांकि, बाजार की उम्मीदों के विपरीत, पेट्रोल का भंडार 19.04 लाख बैरल घटकर 21.21 करोड़ बैरल और डीजल का स्टॉक 49.8 लाख बैरल घटकर 10.36 करोड़ बैरल पर आ गया। शुद्ध आयात में वृद्धि ने कच्चे तेल के भंडार को बढ़ाया। इन विरोधाभासी आंकड़ों के बावजूद गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 1 फीसदी की तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड 78.81 डॉलर और डब्ल्यूटीआई क्रूड 74.26 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। यह तेजी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव (अमेरिका-ईरान सैन्य कार्रवाई की पुष्टि), आपूर्ति अनिश्चितता और महंगाई की चिंताओं का परिणाम है। तनाव बढ़ने से डॉलर इंडेक्स भी 101 के करीब मजबूत हुआ है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें वैश्विक महंगाई की चिंताओं को बढ़ा रही हैं, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों में जल्द कटौती न करने का दबाव बढ़ रहा है। बाजार 2026 तक फेड की ओर से एक बार ब्याज दर बढ़ने की संभावना देख रहा है। निवेशक अब अमेरिका के बेरोजगारी दावों और हाउसिंग डेटा पर नजर बनाए हुए हैं।

एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर किया 6.6 प्रतिशत

मुद्रास्फीति भी बढ़ी फिर भी भारत सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली ।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण ऊर्जा कीमतों में संभावित उछाल को देखते हुए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। एडीबी ने गुरुवार को जारी अपनी एशियाई विकास परिदृश्य रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, इस कटौती के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों से वास्तविक आय पर पड़ने वाले दबाव के कारण यह संशोधन किया गया है। इसके विपरीत, वित्त वर्ष 2027-28 के लिए वृद्धि दर का अनुमान 7.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। एडीबी ने 2026-27 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी बढ़ा दिया है, जो अप्रैल के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर अब 5.2 प्रतिशत हो गया है। 2027-28 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान चार प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी पिछले महीने 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अपना अनुमान 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत किया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी 2026-27 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो पहले के 6.5 प्रतिशत से कम है।

खामेनेई के जनाजे में खूब भीड़ जुटी लेकिन ईरान के बड़े नेता रहे गायब, पूर्व राष्ट्रपति और मुज्तबा भी नहीं दिखे

ईरान पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. उनके जनाजे से ईरान की कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां नदारद रहीं, इससे उसकी राजनीतिक भविष्य और एकजुटता पर सवाल खड़े गए हैं. खामेनेई के जनाजे में खुद उनके बेटे और सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई भी नदारद रहे.

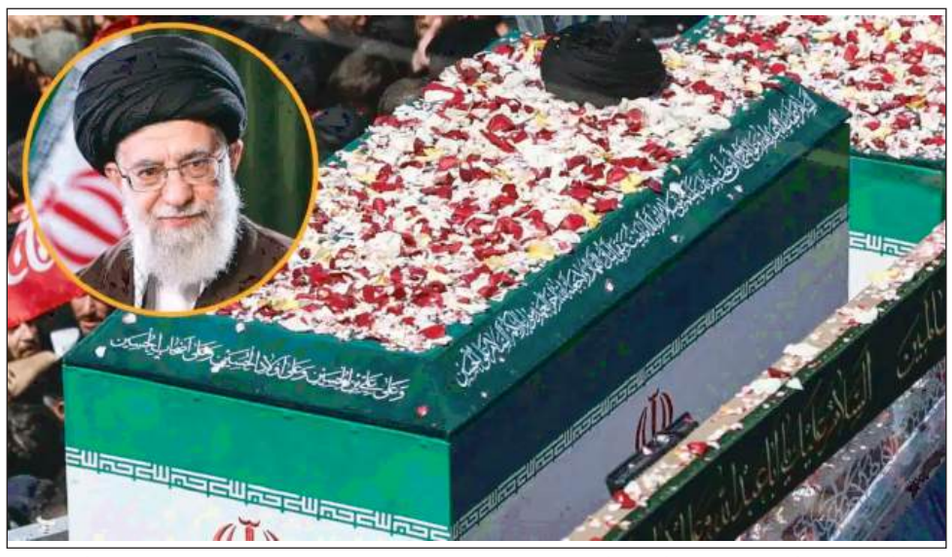

विदेश एजेंसी।
ईरान ने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई विदाई दे दी है. खामेनेई को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी-इजरायली एयरस्ट्राइक में उनकी मौत हो गई थी. खामेनेई के जनाजे के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उनके बेटे मुज्तबा की गैरमौजूदगी की हुई. हालांकि, उनके परिवार के अन्य सदस्य उनके जनाजे में जरूर शामिल हुए.
खामेनेई के जनाजे में नहीं दिखे कई पूर्व राष्ट्रपति
CNN के मुताबिक मुज्तबा सुरक्षा कारणों से जनाजे में शामिल नहीं हुए. लेकिन जनाजे की लाखों लोगों की भीड़ के बीच ईरान के कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों की गैरमौजूदगी ने देश के राजनीतिक भविष्य और एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े हुए. खामेनेई को सुपुर्द-ए-खाक करने के दौरान कई पूर्व राष्ट्रपति नजर नहीं आए. इसमें सुधारवादी नेता मोहम्मद खातमी और हसन रूहानी शामिल हैं. इनके साथ खामेनेई के लंबे समय से मतभेद रहे थे.
पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद भी खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक कार्यक्रम के दौरान नदारद रहे. उनके भी संबंध पूर्व सुप्रीम लीडर के साथ खराब हो गए थे. हालांकि, सोमवार यानी 06 जुलाई को वह खामेनेई को दी जा रही अंतिम विदाई के जुलूस में जरूर दिखाई दिए. सालों तक राजनीतिक सुर्खियों से दूर रहने के बाद वह इस तरह सार्वजनिक तौर पर नजर आए.
खामेनेई की अंतिम विदाई में इन बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने ईरान की राजनीतिक एकजुटता की छवि पर नए सवाल खड़े कर दिए, जिसे ईरानी अधिकारी पेश करना चाहते थे. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है ईरानी अधिकारियों ने जानबूझकर भागीदारी को केवल मौजूदा नेतृत्व के करीबी लोगों तक ही सीमित रखा.

ईरानी नेतृत्व के पास राजनीतिक एकजुटता दिखाने का था शानदार मौका

अमेरिका स्थित ईरान विशेषज्ञ और 'व्हाट ईरानियंस वांट' के लेखक अराश अजीज़ी ने कहा कि आयोजक सुधारवादी राजनीति से जुड़े पूर्व राष्ट्रपतियों को खामेनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम में शामिल कर राजनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन कर सकते थे. लेकिन इसके बजाय उन्होंने कार्यक्रम में सिर्फ शासन के मुख्य और शीर्ष अधिकारियों को ही शामिल करने का फैसला किया.

खामेनेई के जनाजे कार्यक्रम से ईरान यह संदेश देना चाहता था

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली वाएज़ ने बताया कि तेहरान अपने सर्वोच्च नेता को खोने के बाद भी यह दिखाना चाहता था कि उसका सिस्टम लगातार काम करता रहेगा. वह शासन की निरंतरता बनाए रख सकता है. भारी भीड़ और सोच-समझकर आयोजित किए गए अंतिम विदाई कार्यक्रम इसकी ओर इशारा भी करते हैं. लेकिन कार्यक्रम से देश की बड़ी गैर-मौजूदगी दुनिया को यह भी बताती है कि उनका नेतृत्व अभी भी खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं कर रहा है.

चीन बेच रहा अब नकली कंडोम; इन देशों को भेज दी बड़ी खेप, खुलासे के बाद मच गया हड़कंप

विदेश एजेंसी।
यूरोपीय संघ की एंटी-फ्रॉड एजेंसी (OLAF) ने चीन से भेजे गए 2 लाख से अधिक नकली कंडोम की बड़ी खेप का खुलासा किया है। अधिकारियों के अनुसार, इन उत्पादों को मेडिकल डिवाइस के बजाय 'खिलौना (Toy)' घोषित कर यूरोपीय संघ की सख्त गुणवत्ता जांच से बचाकर बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई।जांच में सामने आया कि शिपमेंट के आधिकारिक दस्तावेजों में कंडोम को 'टॉय' बताया गया था। इससे मेडिकल डिवाइस पर लागू होने वाले सुरक्षा मानकों और अनिवार्य परीक्षणों से बचा जा सका। यूरोपीय अधिकारियों ने कहा कि बिना गुणवत्ता परीक्षण वाले नकली कंडोम यौन संचारित संक्रमण (STI), अनचाही गर्भावस्था और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकते हैं। यूरोपीय संघ में कंडोम को मेडिकल डिवाइस माना जाता है। बाजार में बिक्री से पहले इनकी लीकेज टेस्ट, गुणवत्ता जांच, बैक्टीरिया परीक्षण, सुरक्षा मानक, आकार, एक्सपायरी और अन्य तकनीकी परीक्षण किए जाते हैं। नकली खेप इन सभी प्रक्रियाओं से बचकर यूरोप पहुंच गई। जांच के दौरान रोमानिया, सर्बिया और स्पेन में इन नकली कंडोम की बड़ी खेप जब्त की गई।
अधिकारियों के मुताबिक, इन्हें एक प्रसिद्ध ब्रांड के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर असली उत्पाद के रूप में बेचा जा रहा था। हालांकि, जांच के हित में ब्रांड का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। ह्रस्र ने चीन की संबंधित एजेंसियों के सहयोग से जांच कर कथित निर्यातक की पहचान कर ली है। हालांकि, जांच जारी होने के कारण उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि नकली उत्पादों की तस्करी करने वाले गिरोह बेहद संगठित तरीके से काम करते हैं, इसलिए पूरी सप्लाई चेन का पता लगाना चुनौतीपूर्ण है।

इजराइल ने अमेरिका को बताई वो खुफिया रिपोर्ट, जिससे ईरान पर और भड़क सकते हैं ट्रंप

विदेश एजेंसी।
ईरान-अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर है. समझौता टूट गया है. ईरान ने पहले 07 जुलाई को होर्मुज स्ट्रेट में दो जहाजों को निशाना बनाया. जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर बम बरसाए. इसके बाद लगातार दोनों देशों के बीच हमले जारी है. इस बीच इजरायल ने अमेरिका के साथ एक ऐसी खुफिया जानकारी साझा की है, जो इस जंग को और भी खतरनाक स्तर तक भड़का सकता है.

क्या ट्रंप की हत्या की प्लानिंग कर रहा ईरान?

ष्टहृह के मुताबिक उन्हें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि इज़राइल ने अमेरिका को खुफिया जानकारी साझा करते हुए बताया है कि ईरान ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई योजना बनाई है. यह चेतावनी इस हफ्ते मिली. वहीं, ष्टहृह के दूसरे सूत्र ने बताया कि ट्रंप की हत्या की संभावित योजनाओं के बारे में अमेरिका को लगातार खुफिया जानकारी मिल रही थी. लेकिन इजरायल की चेतावनी नई और बड़ी थी.

कहीं इजरायल की ट्रंप के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं

हालांकि, कई अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजरायल की यह रिपोर्ट ट्रंप के फ़ैसले को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है. दरअसल, ट्रंप ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को तेज करने पर विचार कर रहे हैं.

बांग्लादेश में जमात-आवामी लीग को एक साथ निपटाने की तैयारी, क्या है तारिक रहमान सरकार का प्लान

विदेश एजेंसी।
बांग्लादेश की सरकार ने कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर बैन लगाने का तरीका खोज लिया है. गुरुवार (9 जुलाई) को बांग्लादेश की सरकार ने 1971 के मामलों में नए सिरे से केस करने का फैसला किया है. तारिक रहमान की सरकार का कहना है कि यह फैसला आवामी लीग को लेकर किया गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि सरकार के असली निशाने पर जमात ए इस्लामी भी है. यानी बांग्लादेश की 2 बड़ी पार्टी को तारिक रहमान की सरकार एक साथ निपटाना चाहती है.
पिछले दिनों बीएनपी के महासचिव और सरकार में मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बीएनपी पर प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया था. वहींगृह मंत्री सलाहुद्दीन चौधरी ने कहा है कि हम 1971 के फाइलों को फिर से खोलेंगे. हम इतिहास में जितने भी बड़े कांड हुए हैं, उसकी जांच कराएंगे. इसी आधार पर आवामी लीग को बैन किया जाएगा.
निशाने पर जमात क्यों?
1. जमात ए इस्लामी को बांग्लादेश में पाकिस्तान परस्त पार्टी के तौर पर देखा जाता है. 1971 में जमात के नेताओं ने बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था. शेख हसीना सरकार के दौरान जमात पर प्रतिबंध लगा था.
2. जमात का दबदबा लगातार बढ़ रहा है. यह बीएनपी के लिए खतरा है. जमात के नेता बीएनपी के वोटों में सेंध लगाने के लिए लगातार एक्टिव हैं. खुद को जमात के नेता राष्ट्रवादी बताकर सियासी तौर पर मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं.
3. बांग्लादेश की सियासत में विपक्ष को खत्म करने की परंपरा रही है. आवामी लीग के दौरान बीएनपी को काफी कमजोर किया गया था. अभी जमात मुख्य विपक्षी पार्टी है.
सरकार पर लगातार हमलावर
जमात ए इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान तारिक रहमान की सरकार पर लगातार हमलावर हैं. शफीकुर ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी को साजिश के तहत हराया गया. इस साजिश में यूनुस की सरकार शामिल थी. हम अभी सरकार में होते, लेकिन हमें विपक्ष में बैठाया गया.
शफीकुर अक्सर अपने भाषणों में तारिक रहमान को शहजादा उपनाम से संबोधित करते हैं. दरअसल, तारिक की मां खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और पिता जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं.

फ्रांसीसी अदालत से मरीन ले पेन को राहत, जानें कोर्ट ने क्या रखी शर्त; राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर संशय

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस की दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को 2027 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की दिशा में बड़ी राहत मिली है। हालांकि, अपील अदालत ने साफ किया है कि उन्हें अपनी सजा के तहत घर पर रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी ब्रेसलेट पहनना होगा। जबकि ले पेन पहले ही कह चुकी हैं कि इस शर्त के साथ चुनाव प्रचार करना उनके लिए स्वीकार्य नहीं होगा। पेरिस की अपील अदालत ने मंगलवार को ले पेन को यूरोपीय संसद के धन के गबन (गबन/दुरुपयोग) के मामले में दोषी माना, लेकिन उनकी सजा में कुछ राहत दी। अदालत ने सार्वजनिक पद संभालने पर लगी रोक को पांच साल से घटाकर 45 महीने कर दिया। इनमें से दो-तिहाई अवधि निलंबित रहेगी। इसके अलावा, उनकी जेल की सजा भी चार साल से घटाकर तीन साल कर दी गई। इनमें से दो साल की सजा निलंबित रहेगी, जबकि एक साल की सजा उन्हें घर पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी ब्रेसलेट पहनकर पूरी करनी होगी। यह मामला 2004 से 2016 के बीच का है। आरोप है कि ले पेन और उनकी पार्टी नेशनल रैली के अन्य नेताओं ने यूरोपीय संसद के उन फंड

का गलत इस्तेमाल किया, जो संसदीय सहायकों के वेतन के लिए दिए गए थे। आरोप के अनुसार, इस धन से पार्टी के कर्मचारियों को भुगतान किया गया। मार्च 2025 में निचली अदालत ने ले पेन को इस मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल की जेल और पांच साल तक कोई निर्वाचित पद नहीं संभालने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी। 57 वर्षीय मरीन ले पेन लगातार सभी आरोपों से इनकार करती रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। वह 2027 में फ्रांस के राष्ट्रपति पद के लिए चौथी बार चुनाव लड़ना चाहती हैं।

लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को अमेरिका-कनाडा ने निज्जर हत्याकांड का आरोपी बनाया

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने भारत में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ पर नवंबर 2023 में कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आदेश देने का आरोप लगाया है.

लॉस एंजिल्स में मंगलवार को जारी एक संघीय आरोप पत्र के अनुसार बिश्नोई ने तीन साल पहले 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक सिख मंदिर के बाहर निज्जर की हत्या का आदेश दिया था. ऑपरेशन हार्डबॉल' नाम के एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन में अमेरिका, कनाडा और यूरोप की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें से 11 कैलिफ़ोर्निया में थे जो भारत के तीन ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप से जुड़े थे. उन पर निज्जर की हत्या समेत कई क्रिमिनल कामों का

आरोप था. अमेरिकी फर्स्ट असिस्टेंट अटॉर्नी बिल एसेली ने लॉस एंजिल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'एक साथ काम करते हुए अमेरिका, कनाडा, यूरोप और एशिया में लॉ एनफोर्समेंट इन क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन को टारगेट करने और खत्म करने के लिए पक्का इरादा कर चुकी है, चाहे वे कहीं भी काम करते हों. इन गुंडों के लिए कोई सेफ जगह नहीं है.' निज्जर की हत्या से भारत और कनाडा के बीच आपसी रिश्ते खराब हो गए थे, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नई दिल्ली सरकार को इस हत्या से जोड़ने की कोशिश की थी. भारत ने इन दावों को 'बेतुका और जानबूझकर किया गया' बताकर खारिज कर दिया था. मौजूदा कार्रवाई भारतीय क्राइम सिंडिकेट की सालों से चल रही फेडरल जांच का नतीजा है, जो रैकेटियरिंग, टारगेटेड किलिंग, शूटिंग, जबरन वसूली, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी और दुनिया भर में दूसरे ऐसे अपराधों में शामिल हैं, जिनका असर खासकर भारतीय प्रवासियों पर महसूस किया जाता है. कुल मिलाकर, 37 आरोपियों पर जिनमें दो ऐसे आरोपी भी शामिल हैं जो भारत में जेल में रहते हुए अपने ग्लोबल क्रिमिनल सिंडिकेट चलाते थे मंगलवार को खोले गए तीन चार्जशीट में आरोप लगाए गए. अमेरिका में गिरफ्तार किए गए लोग कैलिफ़ोर्निया में 11 के अलावा, एक को इंडियाना में और एक को जॉर्जिया में पकड़ा गया - आज फेडरल कोर्ट में अपनी पहली पेशी पर आ सकते हैं. कनाडा में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक को स्पेन में गिरफ्तार किया गया, और सात आरोपी पहले से ही कस्टडी में थे. एजेंसियां ??10 भगोड़ों की तलाश कर रही हैं. सात अमेरिका में दो भारत में और एक यूरोप में. बिश्नोई पहले से ही भारत की जेल में है, जबकि उसका साथी गोल्डी बरार अभी भी फरार है. एफबीआई के लॉस एंजिल्स फील्ड ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर इन चार्ज पैट्रिक ग्रैडी ने कहा, 'आज (मंगलवार) का कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन तीन क्रूर ट्रांसनेशनल संगठनों के केंद्र पर हमला करता है, जिन्होंने अमेरिका और विदेशों में हिंसा के क्रूर कामों के ज़रिए परिवारों को आतंकित किया है, समुदायों का शोषण किया है।

होर्मुज स्ट्रेट में तीन टैंकरों पर हमले, सऊदी और कतर के जहाजों को नुकसान

लंदन, एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने मंगलवार को बताया कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर तीन अलग-अलग हमले हुए हैं। इन तीनों घटनाओं में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पहली घटना की जानकारी यूकेएमटीओ को सोमवार रात 2119 यूटीसी पर मिली। इसमें बताया गया कि ओमान के लिमाह से करीब आठ समुद्री मील पूर्व में दक्षिण की ओर जा रहे एक टैंकर के बाईं तरफ एक अज्ञात वस्तु टकराई, जिससे उसमें आग लग गई। दूसरी घटना की जानकारी मंगलवार को दी गई। इसमें एक टैंकर को किसी अज्ञात वस्तु से नुकसान पहुंचने की बात कही गई और माना जा रहा है कि उसके ढांचे को नुकसान हुआ है। तीसरी और सबसे नई घटना की जानकारी यूकेएमटीओ को मंगलवार को 1305 यूटीसी पर मिली। इसमें बताया गया कि एक और टैंकर को ड्रोन से हमला किया

गया, जिससे उसे हल्का ढांचागत नुकसान हुआ। यह जहाज अभी भी अपने अगले बंदरगाह की ओर जा रहा था। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार, तीन में से दो जहाजों की पहचान हो चुकी है। इनमें से एक सऊदी अरब के झंडे वाला कच्चे तेल का टैंकर है, जबकि दूसरा कतर का तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टैंकर है। इससे पहले मंगलवार को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना ने दो ऐसे टैंकरों को निशाना बनाया था, जो अमेरिका समर्थित ओमानी रास्ते से होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया कि इन जहाजों ने चेतावनी नहीं मानी थी। फार्स न्यूज एजेंसी ने स्वतंत्र सैन्य पर्यवेक्षक मेन्चोसिंट के 'एक्स' अकाउंट पर साझा की गई सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि समुद्री यातायात की जानकारी से पता चला कि इन दो टैंकरों पर हमले के बाद जापान, भारत और पश्चिमी देशों के कई अन्य जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया और जलडमरूमध्य पार करने के लिए ईरान की ओर से बताए गए रास्ते का इस्तेमाल किया। मंगलवार को मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि कतर का एक एलएनजी टैंकर और सऊदी अरब का एक कच्चे तेल का टैंकर होर्मुज स्ट्रेट के पास आईआरजीसी की ओर से किए गए कथित मिसाइल हमलों में क्षतिग्रस्त हुए। कतर के जहाज की पहचान अल रेकय्यात के रूप में की गई है। रिपोर्टों के अनुसार, हमला होने के बाद इस जहाज ने मदद के लिए आपातकालीन संकेत भेजे। कतर ने मंगलवार को अल-रेकय्यात पर हुए हमले की निंदा की। कतर ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और समुद्री यातायात तथा दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने 'एक्स' पर जारी बयान में कहा कि कतर इस हमले और इससे होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए ईरान को पूरी तरह कानूनी रूप से जिम्मेदार मानता है।

पाकिस्तान के शारजाह से कराची जा रहा कार्गो विमान लापता, क्या समुद्र में गिरा बोइंग 737?

शारजाह , एजेंसी। पाकिस्तान में मंगलवार रात को शारजाह से कराजी जा रहे बोइंग 737 मालवाहक विमान का हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क टूट गया। विमान के पायलट ने पहले नेविगेशन सिस्टम में खराबी की जानकारी दी थी। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया। विमान में पांच चालक दल के सदस्य सवार थे।

पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या बताया : पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि के2 एयरवेज द्वारा संचालित 27 साल पुराने परिवर्तित मालवाहक विमान ने कराची की ओर उड़ान भरते समय पाकिस्तानी मानक समय के अनुसार रात 9:18 बजे नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना दी।

रडार सिस्टम में क्या दिखा : अधिकारियों के अनुसार, समस्या की सूचना मिलने के बाद स्थानीय हवाई यातायात नियंत्रकों ने विमान को निर्देशित करने का प्रयास किया। हालांकि, रडार सिस्टम ने लगभग तीन मिनट बाद विमान को तेजी से नीचे उतरते हुए दिखाया और विमान से संपर्क टूट गया। अधिकारियों ने बताया कि उस समय विमान कराची से लगभग 155 समुद्री मील (287 किमी) पश्चिम में था।

फ्लाइटराडार24 ने क्या बताया : पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि लापता विमान का पता लगाने के लिए उसने अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से समुद्र में एक समन्वित खोज और बचाव अभियान शुरू किया है। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइटराडार24 के अनुसार, प्रारंभिक उड़ान डेटा से संकेत मिलता है कि विमान कराची के दक्षिण-पश्चिम में समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। संभवत ऊंचाई में कई तीव्र परिवर्तनों के बाद और फिर अंतिम तेज अवरोहण के कारण।

विमान समुद्र तल से कितना ऊपर था : स्थानीय प्रसारक जियो न्यूज के अनुसार, विमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ओरमारा के पास अरब सागर के ऊपर उड़ान भरते समय लापता हो गया। फ्लाइटराडार24 ने बताया कि उड़ान डेटा से पता चलता है कि विमान ने पहले ऊंचाई खोई, फिर थोड़ी देर के लिए ऊपर चढ़ा और उसके बाद अचानक और तेजी से नीचे गिरने लगा। सेवा ने आगे बताया कि आखिरी डेटा के अनुसार विमान समुद्र तल से 1,100 फीट ऊपर था। उसकी ऊर्ध्वाधर गिरावट की दर माइनस 22,400 फीट प्रति मिनट थी, जो कि एक अत्यंत तीव्र और असामान्य गिरावट दर है।

क्या है बोइंग 737 : लापता विमान बोइंग 737-400 था। यह निजी मालवाहक एयरलाइन के2 एयरवेज का एकमात्र विमान था। एयरलाइन ने इस विमान को 2024 में सेवा में शामिल किया था। फ्लाइटराडार24 के अनुसार, यह विमान मूल रूप से 1999 में रूस की एयरोफ्लोट के साथ एक यात्री जेट के रूप में सेवा में आया था, जिसे 2012 में एक मालवाहक विमान में परिवर्तित कर दिया गया था।

श्रीलंका की जेल में ड्रग माफिया का खूनी खेल, दो गुटों के संघर्ष में 26 लोगों की दर्दनाक मौत

कोलंबो , एजेंसी। कोलंबो के पास स्थित जेल में हुई यह घातक झड़प श्रीलंका की जेल व्यवस्था में व्याप्त गहरी समस्याओं, जैसे क्षमता से अधिक कैदी और सुरक्षा चूक, को उजागर करती है। 26 मौतों के बाद, अब सरकार पर जेलों में अवैध गतिविधियों को रोकने और सुरक्षा सुधारों को लागू करने का दबाव बढ़ गया है।

श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के करीब स्थित नेगोम्बो जेल में हुई हिंसक झड़प ने पूरे देश को झकझोर दिया हैं। जेल के भीतर दो गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते बड़े संघर्ष में बदल गया, जिसमें कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में जेल के कर्मचारी और कैदी दोनों शामिल हैं। मौजद जानकारी के अनसार यह हिंसा रविवार को शुरू हुई थी और सोमवार तक जारी रही। हालात बिगड़ने के बाद सुरक्षा बलों को जेल परिसर में अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ी। कई घंटों की कोशिशों के बाद स्थिति पर काबू पाया गया और अब जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई।

श्रीलंका के न्याय मंत्री हर्षणा नानायक्कारा ने इस घटना की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि जेल विभाग उनके मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए वह इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने बताया कि इस हिंसा में सात जेल अधिकारियों और 19 कैदियों की मौत हुई हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बता

दें कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जेल के भीतर कथित तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक समूह और उसका विरोध करने वाले दूसरे समूह के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद ने बाद में हिंसक रूप ले लिया। हालांकि जांच एजेंसियां अभी सभी पहलुओं की विस्तार से जांच कर रही हैं और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। गौरतलब है कि श्रीलंका की कई जेलों में पिछले कुछ वर्षों से क्षमता से अधिक कैदियों की मौजूदगी, सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियां और जेल के भीतर अवैध गतिविधियों को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भी कई बार जेलों में सुधार और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की मांग की हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जेल के भीतर संगठित अवैध गतिविधियां सक्रिय रहती हैं, तो इस तरह के टकराव की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ जेल प्रशासन की निगरानी और खुफिया तंत्र को भी अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत मानी जाती है। घटना में घायल हुए 100 से अधिक लोगों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। श्रीलंका सरकार ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि जेल के भीतर कथित अवैध गतिविधियां किस प्रकार संचालित हो रही थीं और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई है। इस घटना के बाद श्रीलंका की जेल व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में आ गई है। सरकार पर अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, जेलों में भीड़ कम करने और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने का दबाव बढ गया है।

2029 तक लागू हो सकती है 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' व्यवस्था: संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष

पणजी, 10 जुलाई। एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयकों की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर काम कर रही है, जिससे एक राष्ट्र, एक चुनाव सुधार को वर्ष 2029 के आम चुनाव तक पूरी तरह लागू किया जा सके। समिति के अध्यक्ष पी. पी. चौधरी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

गोवा में समिति की दो दिवसीय बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में पी. पी. चौधरी ने दावा किया कि अब तक जिन नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों से राय ली गई है, उनमें से लगभग 99 प्रतिशत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उनका कहना है कि बार-बार चुनाव होने से देश को लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है, जिसे इस व्यवस्था से कम किया जा सकता है।

समिति ने गोवा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार-विमर्श शुरू किया। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर एक साथ चुनाव लागू करने में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की गई।

पी. पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ अनौपचारिक चर्चा में इस बात पर विचार किया गया कि एक राष्ट्र, एक चुनाव को किस प्रकार लागू किया जा सकता है, इसके सामने कौन-कौन सी चुनौतियां हैं और सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य संतुलन बनाए रखते हुए उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है।

उन्होंने बताया कि समिति गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों का दौरा कर चुकी है। इन दौरों के दौरान संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों से विचार-विमर्श किया गया।

राजस्थान के पाली से भाजपा सांसद चौधरी ने कहा कि जिन लोगों से अब तक चर्चा की गई है, उनमें से लगभग 99 प्रतिशत ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया है। अब प्रयास यह है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए स्वीकार्य व्यवस्था विकसित की जाए।

उन्होंने कहा कि समिति विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है और संभावना है कि वर्ष 2029 के आम चुनाव तक यह व्यवस्था लागू की जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि राजनीतिक दल और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री स्वेच्छा से अपने चुनावी चक्र को एक समान करने पर सहमत होते हैं, तो वर्ष 2029 से पहले भी कुछ राज्यों को इस व्यवस्था के अनुरूप लाया जा सकता है। प्रस्ताव के आर्थिक पक्ष पर जोर देते हुए पी. पी. चौधरी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत अध्ययन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अध्ययन के अनुसार अलग-अलग समय पर चुनाव कराने से देश को लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है, जबकि एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समान स्तर का लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रह गए हैं। देश के किसी भी हिस्से में चुनाव होने का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था परस्पर जुड़ी हुई है। गोवा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि किसी बड़े राज्य में चुनाव होने पर गोवा में आने वाले पर्यटकों की संख्या प्रभावित होती है, जबकि गोवा में चुनाव होने का सीधा असर राज्य के पर्यटन उद्योग पर पड़ता है।

हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप करने वाले क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करा पाएंगे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का भी किया अनावरण

सपा वाले वक्फ के नाम पर जिस श्रृंग्वेरपुर में कब्जा करा रहे थे, वहां भाजपा सरकार ने भगवान राम व निषादराज के मिलन की भव्य प्रतिमा व स्मारक का निर्माण कराया: सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण/शिलान्यास

आस्था का दिखावा करने वाले दलों पर सीएम योगी ने किया प्रहार

अयोध्या, 10 जुलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था का दिखावा करने वाले दलों पर रामनगरी में कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी, लेकिन क्या सपा, कांग्रेस या अन्य सरकारें जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएंगी। यदि नहीं करा पाएंगी तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों कराया गया था? आस्था का दिखावा कर रहे लोगों ने यह पाप किया था, जबकि भाजपा ने अयोध्या को सनातन धर्म की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित किया।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। इस अवसर पर अयोध्या के विकास कार्यों पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया और लोकार्पण व शिलान्यास वाली तमाम योजनाओं का जिक्र कर इनका श्रेय जनता व जनप्रतिनिधियों को दिया।

सीएम ने कहा कि बीकापुर विधायक ने पिछली बार ग्राम पंचायत खिरौनी-सुचित्तागंज को नगर पंचायत बनवाया था। अब उनकी मांग पर यह नगर पंचायत मां ज्वाला देवी के नाम पर होगी। समाजवादी पार्टी का असली चरित्र सभी ने देखा होगा, जब इनके नमूने चेयरमैन ने भदरसा में गुस्ताखी की थी। भदरसा नगर पंचायत अब भरतनगर भरतकुंड होगा। भाई-भाई का संबंध भरत जी से सीखिए। 14 वर्ष तक भरतकुंड के पास रहकर उन्होंने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया। भगवान राम की चरण पादुकाएं अयोध्या का संचालन कर रही थीं। भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है, लेकिन अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न जैसे भाई हुए। चारों दिशाओं में अयोध्या की पहचान आज भी मौजूद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीयत साफ और नीति स्पष्ट हो तो नियंता भी साथ देता है। प्रभु राम और पवनसुत के आशीर्वाद से सभी कार्य अपने आप बढ़ते हैं। बीकापुरवासियों ने अच्छा विधायक चुना तो विकास दौड़ता दिखाई देता है।

जैसे अयोध्या का वैभव देश में चरम पर दिखाई देता है, वैसे ही बीकापुर में भी विकास की योजनाएं दिखाई दे रही हैं। सक्रिय जनप्रतिनिधि जब विकास में रूचि लेते हैं तो परिणाम वैसे ही सकारात्मक आते हैं, जैसे आज अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर, गोसाईगंज, रुधौली में दिखाई दे रहे हैं।

सीएम ने कहा कि 19 जून को हमने रुदौली में विकास योजनाओं की सौगात दी थी। पहले जो असंभव था, वह इन जनप्रतिनिधियों के कारण संभव हो पाया। लंबे समय तक सड़क, बिजली, पानी नहीं मिलने से अयोध्या उपेक्षित होने के साथ विकास से वंचित रहती थी। व्यवस्था न होने से श्रद्धालु मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल रहता था, लेकिन अब मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को अभिसिंचित करती है।

सीएम ने कहा कि अयोध्या अब वैभवशाली और तीनों लोकों से न्यारी है। गलियां चमक रही हैं, लाइट भी रहती है। सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या पीएम मोदी के विजन के अनुरूप सोलर सिटी बन गई है। नए घाट से लेकर गुप्तार घाट तक घाटों की श्रृंखला है। सीएम ने सभी का आह्वान किया कि कभी उपेक्षित रहे गुप्तार घाट में अब परिवार के साथ घूमने जाइए। हमने सूरजकुंड का पुनरुद्धार किया। स्थानीय विधायक के प्रस्ताव पर भरतकुंड का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है।

सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग एयरपोर्ट के नाम पर गुमराह करते थे, लेकिन अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। अयोध्या सभी शहरों के साथ जुड़ गई है। सपा व कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर पाए, इसलिए अयोध्या का विरोध कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार ने निषादराज के नाम पर रैनबसेरा और मां शबरी के नाम पर भोजनालय बनवाकर समरसता फैलाई। हरिद्वार में हरि की पैड़ी की तरह ही अयोध्या में राम की पैड़ी दिख रही है। रोज सरयू मैया की आरती होती है। सपा जिस वक्फ के नाम पर श्रृंग्वेरपुर में कब्जा करा रही थी, भाजपा सरकार ने वहां भगवान राम व निषादराज के मिलन की भव्य प्रतिमा व स्मारक बनाया है।

स्थानीय समाचार

डिजिटल भारत निधि की समीक्षा- डीसी कठुआ ने पहाड़ी क्षेत्रों में तेज इंटरनेट विस्तार पर दिया जोर

कठुआ, 10 जुलाई (हि.स.)। डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने शुक्रवार को डिजिटल भारत निधि के तहत ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में बीएसएनएल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बीएसएनएल अधिकारियों ने बताया कि कठुआ, हीरानगर, मढ़हीन और डिंगा अंब के पंचायत घरों तक फाइबर इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जा चुकी है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने का कार्य जारी है। साथ ही समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बसोहली, बिलावर और बनी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के विस्तार पर विशेष जोर देते हुए कार्य में तेजी लाने और समयबद्ध तरीके से परियोजना पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम लोगों को इस सुविधा के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी बल दिया।

कुलगाम की विश्वो नदी में डूबने से एक लड़के की मौत

कुलगाम, 10 जुलाई (हिं.स.)। शुक्रवार को कुलगाम जि़ले के हसनपोरा बाग इलाके में विश्वो नदी में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। एक अधिकारी बताया कि लड़का गलती से नदी में गिर गया और डूब गया। स्थानीय लोगों ने उसे पानी से बाहर निकाला और तुरंत बिजबेहरा के सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हसनपोरा बाग, कुलगाम के रहने वाले शौकत अहमद गनी के बेटे हाजि़म शौकत के तौर पर हुई है। इस बीच, पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है।

सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता इंजीनियर राजिंदर कुमार के खिलाफ दिया नियमित विभागीय जांच का आदेश

जम्मू, 10 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता इंजीनियर राजिंदर कुमार के खिलाफ नियमित विभागीय जांच का आदेश दिया है जो लोक निर्माण (आर एंड बी) निर्माण प्रभाग-चार एसएसए/आरएमएसए (समग्र प्रभाग तीन और चार) जम्मू में तैनात थे।

लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग द्वारा जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार पीएमजीएसवाई सर्कल जम्मू के प्रभारी अधीक्षण अभियंता इंजीनियर अभिषेक गुप्ता को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है जबकि पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी) प्रभाग बख्शी नगर के प्रभारी कार्यकारी अभियंता इंजीनियर संदीप गुप्ता प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से अमरनाथ यात्रा के लिए आए मध्य प्रदेश के 5 यात्री घायल

उधमपुर, 10 जुलाई । शुक्रवार सुबह एनएच-44 के उधमपुर-चेनानी हिस्से में टोल्डी नाला के पास एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से अमरनाथ यात्रा के 5 यात्री घायल हो गए जिनमें से एक की हालत गंभीर है। यह हादसा सुबह एमपी 13ंभाई-2836 नंबर की अर्टिगा गाड़ी के साथ हुआ।

अधिकारियों ने जानकारी देते बताया कि घायल सभी पांचों लोग मध्य प्रदेश से अमरनाथ यात्रा पर आए यात्री हैं। इनमें से एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन, गोरखा 4/3, सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया

। घायलों को इलाज के लिए तुरंत एसोसिएटेड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर ले जाया गया।

घटना की पुष्टि करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने उधमपुर के डीसी मिंगा शेरपा से बात की।

उन्होंने बताया कि 5 लोग घायल हुए हैं जिनमें से एक महिला गंभीर रूप से घायल है और इसलिए उसे तुरंत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू रेफर कर दिया गया है।

मंत्री ने कहा कि हर संभव मदद दी जा रही है। उनका ऑफिस लगातार संपर्क में है।

विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकारी आईटीआई लेह में एकीकृत प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया

लेह, 10 जुलाई। लद्दाख में तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और युवाओं को उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), लेह में **एकीकृत प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र - सृजन** का उद्घाटन किया। यह केंद्र भारत फोर्ज लिमिटेड की सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड (केएसएसएल) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत स्थापित किया गया है। इसमें साइंटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड तकनीकी सहयोगी की भूमिका निभा रही है। एक करोड़ एक लाख रुपये से अधिक की लागत से विकसित इस केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशाला अवसंरचना, उद्योग स्तर के उपकरण, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर तथा आधुनिक प्रशिक्षण प्रणालियां स्थापित की गई हैं, ताकि लद्दाख के युवाओं को विश्वस्तरीय तकनीकी शिक्षा और उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। नवनिर्मित उत्कृष्टता केंद्र में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी), इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी, न्यूमैटिक्स, हाइड्रोलिक्स, औद्योगिक स्वचालन, इंजीनियरिंग सिमुलेशन सिस्टम तथा इंडस्ट्री 4.0 जैसी आधुनिक तकनीकों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे प्रशिक्षुओं को आधुनिक विनिर्माण और इंजीनियरिंग उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक कौशल प्राप्त होगा। उपराज्यपाल ने केंद्र में प्रशिक्षण शुरू करने वाले 22 प्रशिक्षुओं के पहले बैच से भी संवाद किया। इन प्रशिक्षुओं ने दो माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षु स्वयं प्रयोगशाला के लिए सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली का डिजाइन तैयार करेंगे और उसकी स्थापना भी करेंगे।

यह पहल प्रशिक्षुओं को नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगी। साथ ही प्रयोगशाला को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा हरित एवं सतत ऊर्जा समाधान को भी बढ़ावा देगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ ऊर्जा विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इस अवसर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन केवल एक आधुनिक प्रयोगशाला की शुरुआत नहीं, बल्कि लद्दाख के युवाओं के लिए नई आकांक्षाओं, नए अवसरों और उज्ज्वल भविष्य का शुभारंभ है।

डीसी और डीआईजी ने जीएमसी उधमपुर का दौरा कर घायल अमरनाथ यात्रियों के उपचार की समीक्षा की

उधमपुर, 10 जुलाई। उपायुक्त उधमपुर मिंगा शेरपा और उप महानिरीक्षक पुलिस (उधमपुर-रियासी रेंज) शिव कुमार ने आज सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) उधमपुर का दौरा कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोल्दी नाला के पास सड़क दुर्घटना में घायल हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा के श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की।

उपायुक्त और डीआईजी ने घायल श्रद्धालुओं के उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। बताया गया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक मारुति कार तोल्दी नाला के पास सड़क से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसमें सवार यात्री घायल हो गए।

दौरे के दौरान अधिकारियों ने घायल श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और अस्पताल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे उपचार की समीक्षा की। उपायुक्त ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा, चौबीसों घंटे चिकित्सकीय निगरानी तथा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उपायुक्त ने सुरक्षा बलों और चिकित्सा कर्मियों द्वारा समय पर राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने की सराहना की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को प्रत्येक मरीज की स्थिति पर लगातार नजर रखने तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त प्रेम सिंह, चिकित्सक तथा अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

डीसी ने बीआरओ परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

उधमपुर, 10 जुलाई। उपायुक्त उधमपुर मिंगा शेरपा ने आज अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की अध्यक्षता कर जिले में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा संचालित प्रमुख सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने धार सड़क सहित अन्य चल रही बीआरओ परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी एजेंसियों को पर्याप्त मानव संसाधन और मशीनरी तैनात कर कार्य में तेजी लाने तथा सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

यात्रियों की सुविधा हेतु छपरा - पठानकोट - छपरा साप्ताहिक विशेष ट्रेन के फेरों में विस्तार

***जम्मू,10 जुलाई 2026।** ग्रीष्मकालीन एवं आगामी त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए, तथा यात्रियों की मांग के अनुरूप उत्तर रेलवे, जम्मू मंडल द्वारा ट्रेन संख्या 05193 छपरा - पठानकोट और ट्रेन संख्या 05194 पठानकोट - छपरा साप्ताहिक विशेष ट्रेन के फेरों में अस्थायी विस्तार किया गया है। यह निर्णय यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है।

विवरण अनुसार ट्रेन संख्या 05193 छपरा - पठानकोट साप्ताहिक विशेष जो प्रत्येक *सोमवार को संचालित होती है, पूर्व में 13 जुलाई 2026 तक अधिसूचित थी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस ट्रेन का संचालन 20 जुलाई 2026 से 28 सितंबर 2026 तक* किया जाएगा। इस विस्तारित अवधि में यह गाड़ी कुल *11 फेरे* लगाएगी।

इसी प्रकार वापसी में चलने वाली ट्रेन संख्या 05194 पठानकोट - छपरा साप्ताहिक विशेष जो प्रत्येक *बुधवार* को चलती है, पूर्व में 15 जुलाई 2026 तक अधिसूचित थी। अब इसे *22 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक* बढ़ाया गया है और इस अवधि में भी यह कुल 11 फेरे संचालित करेगी।

जम्मू मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, जम्मू मंडल श्री उचित सिंघल ने बताया कि, द्व卐यात्रियों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए हमने इन विशेष गाड़ियों के फेरों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमारा उद्देश्य है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिले और वे बिना किसी असुविधा के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। रेलवे यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए इस प्रकार के कदम समय-समय पर उठाता रहता है।

कठुआ की बेटी अंजलि देवी ने एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा

कठुआ, 10 जुलाई (हि.स.)। कठुआ की बेटी अंजलि देवी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने न केवल कठुआ बल्कि पूरे जम्मू-कश्मीर और देश का गौरव बढ़ाया है।

जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया ने शुक्रवार को अंजलि देवी के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया और इस ऐतिहासिक उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि अंजलि की साहस, दृढ़ संकल्प और समर्पण की यह मिसाल युवाओं, खासकर बेटियों के लिए एक नई दिशा तय करती है। अंजलि देवी की इस सफलता पर उन्हें और उनके परिवार को बधाई देते हुए जसरोटिया ने कहा कि यह उपलब्धि जम्मू-कश्मीर को वैश्विक पर्वतारोहण के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि यहां के युवाओं में अपार प्रतिभा और जज्बा मौजूद है और अगर मेहनत व लगन हो तो कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं। उन्होंने कहा कि अंजलि देवी की सफलता देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं और सकारात्मक बदलावों का भी प्रतीक है। इन प्रयासों ने महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया है और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए हैं। जसरोटिया ने कहा कि आज भारत की बेटियां रक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, उद्यमिता और पर्वतारोहण जैसे हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। यह एक ऐसे माहौल का परिणाम है, जो उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अंजलि देवी के माता-पिता की भी सराहना करते हुए कहा कि परिवार का सहयोग और त्याग ही ऐसी असाधारण उपलब्धियों की नींव होता है। अंत में विधायक ने अंजलि देवी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह आगे भी देश का नाम रोशन करती रहेंगी और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी।